सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 78, नई दिल्ली । गुरुवार, 30 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है।

03 दिल्ली सरकार ने पानी बर्बादी पर लगाया पहरा पहरा , 200 टीमें तैनात, 2000रू.का जुर्माना

06 कम मतदान क्यों होता है ?

08 भारत निर्वाचन आयुक्त ने तीन आदेश जारी किये

आग लगने की घटना के बाद 300 ई-बसों का होगा ऑडिट , आपूर्ति और संचालन करने वाली संस्था को आदेश जारी

संजय बाटला

अभी तक जिन बसों में आग लगने की बात सामने आती रहीं है, वह सीएनजी की होती थी। ई-बसों के संचालन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) ने 300 ई-बसों का ऑडिट करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में गत वर्ष शामिल हुई इलेक्ट्रिक बस में आग लगने की घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। अभी तक जिन बसों में आग लगने की बात सामने आती रहीं है, वह सीएनजी की होती थी। ई-बसों के संचालन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) ने 300 ई-बसों का ऑडिट करने का आदेश दिया है। बसों की आपूर्ति और संचालन कर रहे ऑपरेटर को ऑडिट कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

राजधानी में कुल 1650 ई-बसों का संचालन हो रहा है। इनमें 1350 बसें डीटीसी के अंतर्गत चल रही हैं। वहीं, 300 बसों का संचालन डीआईएमटीएस कर रहा है। 19 मई को हौज खास में ई-बस में आग लग गई थी। यह बस सिर्फ 14 हजार किलोमीटर चली थी। गनीमत रही कि आग लगने से पहले ही बस से यात्रियों को उतार दिया गया।

हालांकि, बस पूरी तरह जल गई। इस घटना के बाद से लगातार बसों में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण की रोकथाम के लिए बीते साल से ई-बसों का संचालन शुरू हुआ था। ई-बसों को सुरक्षित बताया गया था। वर्तमान में समय में अभी दिल्ली में तापमान और ऊपर जाएगा, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा व बसों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने सभी बसों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया में बसों में लगी लीथियम बैटरी, वायरिंग, मोटर समेत करीब 20 से अधिक मानकों का परीक्षण होगा।

ऑडिट रिपोर्ट की पुरानी रिपोर्ट से होगी तुलना

अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने बसों की आपूर्ति के समय रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था बसों में सभी मानक पूरे हैं। ऐसे में नई ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी तुलना पुरानी रिपोर्ट से की जाएगी। इसके आधार पर बसों के संचालन को सुचारू रखने या बदलाव किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

बस के मोटर के पास से उठा था धुआं

19 मई को जिस ई-बस में आग लगी थी, उसकी प्राथमिक जांच में पता चला है कि बैटरियों में कोई दिक्कत नहीं थी, बस की मोटर के पास से पहले धुआं उठा था और इसके बाद आग लगी। माना जा रहा है कि मोटर के पास लगी तारों के गर्म हो जाने से पहले इंसुलेटर जले और बस के अंदर आग पहुंच गई।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

1 जून से बदलने वाले हैं कई नियम, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

परिवहन विशेष न्यूज

हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें नए सिरे से तय की जाती हैं। पेट्रोलियम कंपनियां इसका एलान महीने के आखिरी दिन मध्यरात्रि को करती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 1 जून 2024 को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी समेत पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव कर सकती है।

नई दिल्ली। हर नए महीने में कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। एक जून 2024 से भी नियमों में बदलाव हो होने वाला है। चिलचिलाती गर्मी के बीच जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर, बैंकों की छुट्टियां, आधार कार्ड में अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में परिवर्तन होने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं एक जून से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं?

एलपीजी सिलेंडर समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें नए सिरे से तय की जाती हैं। पेट्रोलियम कंपनियां इसका एलान महीने के आखिरी दिन मध्यरात्रि को करती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 1 जून 2024 को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी समेत पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव कर सकती है। इससें पहले मई में, पेट्रोलियम कंपनियों ने वाणिज्यिक (कमर्शियल) सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की थी। जून में भी सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक जून से लंबे समय से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव दिख सकता है। हालांकि कीमतें बदलेंगी या नहीं इस पर स्थिति 31 मई 2024 की मध्य रात्रि तक ही साफ हो सकेंगी।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने से मिलेगी निजात

1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। नए महीने से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने की प्रक्रिया अब आसान होने की उम्मीद है। एक जून से आप सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इससे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी।

ट्रैफिक नियम सख्त होंगे

नए यातायात नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के लोगों पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने या उनके वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द तो किया ही जाएगा इसके साथ-साथ 25 साल तक नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा। अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से 2000 रुपये, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये, हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

14 जून तक मुफ्त में कर सकेंगे आधार अपडेट

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के अनुसार, अगर आपने 10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो 14 जून तक आप ऐसा फ्री में कर सकते हैं। यूआईडीएआई पोर्टल पर 14 जून 2024 तक आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया मुफ्त है। अगर आप 14 जून के बाद अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो आपको इसके लिए कुछ शुल्क चुकाना पड़ सकता है। आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे या आधार कार्ड सेंटर पर जाकर भी अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो आपको 50 रुपये शुल्क के तौर पर चुकाना होगा। वहीं, यूआईडीएआई पोर्टल पर जाकर खुद से आधार कार्ड अपडेट करने पर फिलहाल कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ा है।

जून महीने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

जून महीने में बकरीद, वट सावित्री व्रत समेत अलग-अलग पर्व त्योहारों के मौके पर सार्वजनिक और साप्ताहिक छुट्टियां के चलते कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, जून में कुल 12 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के मतदान के कारण जून महीने की पहली तारीख को भी कई राज्यों के कुछ क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। बैंक शाखाएं बंद रहने के दौरान आप बैंक जाकर कोई भी सेवा हासिल नहीं कर सकेंगे। ऐसे में आप अपने बैंकिंग से जुड़े कार्यों को बैंकों की छुट्टियों को देखते हुए प्लान करें यही बेहतर रहेगा। हालांकि एक बार यहां गौर करने वाली है कि जिन दिनों को बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, उन दिनों में भी बैंकों ऑनलाइन सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो होगी ये परेशानी

आयकर विभाग ने हाल में एक अधिसूचना में करदाताओं को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को 31 मई तक आधार के साथ जोड़ने के लिए कहा है ताकि उच्च दर पर कर कटौती से बचा जा सके।मौजूदा नियमों के अनुसार यदि करदाता का पैन उसके आधार से नहीं जुड़ा है, तो स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को एक जून से सामान्य दर से दोगुनी दर से काटा जाना अनिवार्य कर दिया है।

भोपाल: इन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव, ग्रीन लाइट का नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार

भोपाल। मध्य प्रदेश में नौतपा में गर्मी कहर बरपा रही है. तापमान में वृद्धि को देखते हुए मंगलवार से ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों के रुकने के समय को कम कर दिया गया है. राजधानी के कई ट्रैफिक सिग्नल का समय बदला गया है. यातायात पुलिस द्वारा समय में बदलाव से वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिलेगी. चालकों को अब सिग्नल पर एक मिनट से भी कम रुकना पड़ेगा. दोपहिया चालकों को गर्मी और लू में गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

सिग्नल का समय आधा : वाहन चालकों को सड़क पर पहले 110 सेकंड से 120 सेकंड तक रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब ये समय कम कर के 40 सेकंड कर दिया गया है. ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में सिग्नल पर ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े. मंगलवार से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए समय बदला जाएगा, ताकि वाहन चालकों को धूप में ज्यादा देर तक खड़ा न होना पड़े. ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी संजय सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को मुख्यतः जो 2 पहिया चालक हैं, उन्हें गर्मी में परेशान न होना पड़े और गर्मी से थोड़ी राहत पहुंचे, इसलिए ट्रैफिक लाइट का समय कम किया गया है.

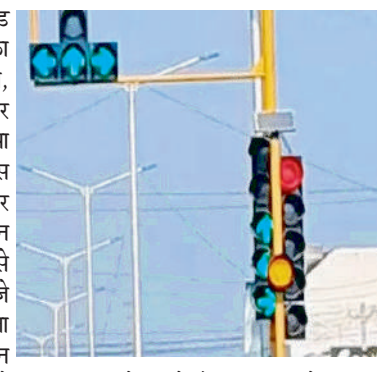

इन चौराहों पर मिलेगी राहत : शहर के कई सिग्नल पर समय का बदलाव किया गया है, जिनमें लालघाटी चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, रेतघाट, सिंधी कॉलोनी चौराहा, कंट्रोल रूम तिराहा, जवाहर चौक चौराहा, ज्योति टॉकीज चौराहा, भोपाल टॉकीज, एमपी नगर थाना चौराहा, रंगमहल चौराहा, प्रभात चौराहा, शौर्य स्मारक चौराहा, भारत माता चौराहा, गोविंदपुरा चौराहा, करोंद चौराहा, जिला कोर्ट चौराहा, आईएसबीटी तिराहा,व्यापम चौराहा और बोर्ड ऑफिस चौराहा भी शामिल है. यातायात पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि सभी यातायात नियमों का पालन करें. अति आवश्यक न हो तो गर्मी में बाहर न निकलें.

मेघदूत सोसाइटी: नोएडा सेक्टर 50 में हरित जीवन और सामुदायिक सहभागिता का एक प्रतीक - अंकुर

परिवहन विशेष न्यूज

मेघदुत सोसाइटी लंबे समय से स्थायी जीवन और सामुदायिक भावना के जीवंत उदाहरण के रूप में खड़ी है, जो प्रकृति, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जीवंतता को मिश्रित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देती है। मेघदुतम पार्क के आसपास 20 ऊंची-ऊंची सोसायटियों के बीच स्थित भूदृश्य और हरी-भरी भूमि बेहद खूबसूरत है और उनकी तस्वीरें अद्भुत और वास्तव में प्राकृतिक हैं।

जो प्रतिदिन 500 से 600 आगंतुकों को आकर्षित करता है।

लगभग 10,000 से 12,000 की संपन्न आबादी के साथ, पार्क मनोरंजन और स्वास्थ्य गतिविधियों का केंद्र बन गया है। जॉगर्स, धावक, योग उत्साही और बच्चे पार्क के हरे-भरे वातावरण में एक अभयारण्य पाते हैं। समूह अभ्यास और अन्य स्वास्थ्य-केंद्रित गतिविधियाँ आम दृश्य हैं, जो शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देने में पार्क की भूमिका को रेखांकित करती हैं।

राजीव सिंह अध्यक्ष, NOFAA - नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के साथ विशेष साक्षात्कार के दौरान उनके खूबसूरत वक्तव्य इस प्रकार हैं:

व्यक्तिगत रूप से, मैं, कुछ समर्पित मित्रों के साथ, मेघदूतम पार्क की स्थापना के समय से ही इससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे प्रयासों ने पार्क को सौ से अधिक मैराथन धावकों और कई साइकिल सवार स्थल में बदल दिया है। हमने समुदाय की बेहतर सेवा के लिए पार्क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में अथक प्रयास किया है। मुख्य सुधारों में एक ओपन जिम की स्थापना, नरम मिट्टी वाले रनिंग ट्रैक का निर्माण और स्वच्छ, कार्यात्मक शौचालयों का प्रावधान शामिल है। हमने बच्चों के खेलने के क्षेत्रों का विकास, फव्वारों का संचालन और सिंचाई के लिए एसटीपी पुनर्नवीनीकृत पानी का उपयोग भी सुनिश्चित किया है। वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ और नियमित वृक्षारोपण स्थिरता के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं।

पार्क की प्राचीन स्थिति को बनाए रखने में नोएडा प्राधिकरण के साथ हमारा सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। परिवर्तन ने न केवल क्षेत्र को सुंदर बनाया है बल्कि प्रवासी और निवासी पक्षियों को भी आकर्षित किया है, जिससे पार्क की जैव विविधता समृद्ध हुई है।

श्री विनोद अग्रवाल द्वारा समर्थित पार्क का एम्फीथिएटर एक सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह समकालीन संगीत और कहानी कहने के सत्र से लेकर पुस्तक प्रदर्शनियों और कला कार्यशालाओं तक कई तरह के कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। ये आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं।

मेघदुत सोसाइटी और सक्रिय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों ने इस समुदाय को ग्रेटर नोएडा के सबसे हरे-भरे और सबसे अधिक प्रकृति-अनुकूल समुदायों में से एक के रूप में स्थापित किया है। हमारी पहल ने एक सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाया है जहां प्रकृति, स्वास्थ्य और संस्कृति पनपती है, जो टिकाऊ जीवन और सामुदायिक जुड़ाव के लिए एक मानक स्थापित करती है।

मेघदूत सोसाइटी इस बात का प्रमाण है कि जब नागरिक एक हरित, स्वस्थ और अधिक जीवंत समुदाय के लिए साझा दृष्टिकोण के साथ एकजुट होते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है।

Indiangreenbuddy@gmail.com

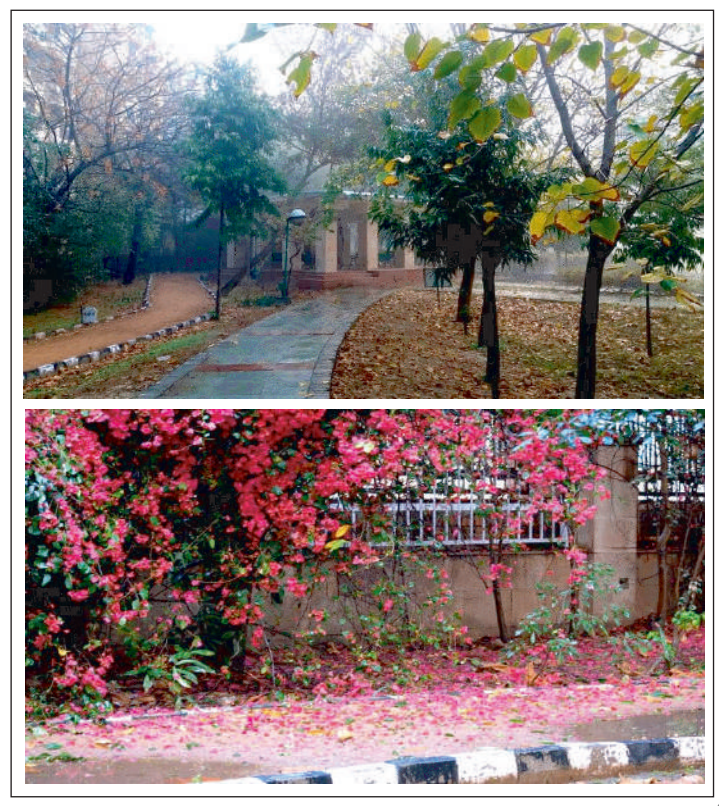

इनसाइड

हार्मोनल बदलाव ही नहीं महिलाओं की इन 5 परेशानियों को भी ठीक करती है कसूरी मेथी, ये होते हैं फायदे

आयुर्वेद में कसूरी मेथी को औषधि माना गया है। इसका उपयोग कई तरह के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कसूरी मेथी का सेवन करने से महिलाओं की हार्मोनल बदलाव ही नहीं महिलाओं की इन 5 परेशानियों को भी ठीक करती है कसूरी मेथी, ये होते हैं फायदे

खाने का स्वाद बढ़ाना हो या खुशबू, कसूरी मेथी का इस्तेमाल हर रसोई में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कसूरी मेथी न सिर्फ खाने का स्वाद अच्छा करती है बल्कि सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को भी ठीक करने में मदद करती हैं। आयुर्वेद में कसूरी मेथी को औषधि माना गया है। इसका उपयोग कई तरह के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कसूरी मेथी का सेवन करने से महिलाओं की कौन सी 5 समस्याएं दूर होती हैं।

प्रेग्नेंसी के बाद भी फायदेमंद-

ऐसी महिलाएं जो बच्चों को स्तनपान करवाती हैं उन्हें कसूरी मेथी का सेवन जरूर करना चाहिए। कसूरी मेथी में पाए जाने वाले तत्व ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में मदद करते हैं।

एनीमिया से करें बचाव-

भारत में ज्यादातर महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। ऐसी महिलाओं के लिए कसूरी मेथी का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। कसूरी मेथी में काफी मात्रा में आयरन मौजूद होता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। शरीर में खून की कमी होने पर अपनी डाइट में कसूरी मेथी को जरूर शामिल करें।

इंफेक्शन से करें बचाव-

पेट के इंफेक्शन से बचाव करने के साथ कसूरी मेथी का सेवन हार्ट, गैसट्रिक और आंतों की समस्याएं को भी दूर रखने में मदद करता है। अगर किसी महिला को पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो वो कसूरी मेथी की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर में नींबू की कुछ बूंदें डालकर इसे उबले हुए पानी के साथ लें।

हार्मोनल बदलाव करे ठीक-

महिलाओं की बॉडी में जीवनभर हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं। जिसके पीछे पीरियड्स, गर्भावस्था, मेनोपॉज आदि कारण जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में कसूरी मेथी का सेवन हार्मोनल बदलाव को कंट्रोल करके उससे होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद करता है।

डायबिटीज करें कंट्रोल-

खानपान में गड़बड़ी का सीधा असर आपके ब्लड शुगर पर पड़ने लगता है। इसे नियंत्रित करने के लिए मेथी का प्रयोग करें। मेथी में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यह टाइप-2 डायबिटीज होने की संभावना को भी कम करता है।

पैरों के तलवों में छिपा है आपका भविष्य:

क्या आप जानते हैं कि पैरों की लकीरें भी हाथों की लकीरों के समान बेहद बलवान होती है। आमतौर पर आपने सुना और देखा है कि लोग अपने भविष्य को लेकर जब जब चिंतित होते हैं, तो वे तब तब उसके उपाय के लिए ज्योतिषविदों की शरण में पहुंचते हैं और अपने हाथ की रेखाओं के जरिए अपने भविष्य और वर्तमान का आकलन करते हैं। मगर इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपके पैर भी आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं और यहां तक की आपके व्यापार या विवाह से संबंधी कई तरह की जानकारी खुद में समेटे हुए हैं। पैर में नजर आने वाली लकीरों को आप कभी हल्के में मत लें क्योंकि कहीं न कहीं ये लकीरें ही हमारा भाग्य लिखने में सक्षम साबित होती है। तो आईए जानते है कि पैरों के तलवे किस प्रकार व्यक्ति के भविष्य की गाथा सुनाते हैं। वो लोग जिनके पैरों के तलवे एक दम सीधे या फ्लैट होते हैं और जिनके पैर सीधा जमीन की सतह को छूते हैं, वे लोग खुली विचारधारा के होते हैं। वे काम के प्रति बेहद सतर्क और परिश्रमी होते हैं। वे हमेशा अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते है और अपने विचारों से अन्य लोगों का दिल जीतने की भी उनमें एक अनोखी प्रकार की विधा होती है। इसके अलावा इन लोगों को अपने व्यवहार और दया भावना के लिए समाज में काफी सम्मान मिलता है। अपनी अच्छी सोच की बदौलत इन्हें जीवन में खूब सफलता हासिल होती है।

बच्चे के साथ ऑफिस को मैनेज करने में होती है परेशानी 5 टिप्स करें फॉलो, आसान हो जाएगी जिंदगी

ऑफिस गोइंग वूमन के लिए काम के साथ-साथ बच्चे को संभालना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है. ऐसे में कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स आपके बेहद काम आ सकती हैं. शेड्यूल सेट करने से लेकर शॉर्टकट फॉलो करने और खुद के लिए समय निकाल कर महिलाएं ऑफिस और बच्चों को वक्त देने के साथ-साथ लाइफ को भी फुल एन्जॉय कर सकती हैं.

वर्किंग वूमन के लिए घर के साथ-साथ ऑफिस संभालना काफी मुश्किल टास्क होता है. खासकर घर में बच्चे होने से महिलाओं की परेशानी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में महिलाओं को बच्चे के साथ ऑफिस को भी मैनेज करना पड़ता है. हालांकि अगर आप चाहें तो कुछ ईजी मैनेजमेंट टिप्स (Time management tips) फॉलो करके बिना किसी परेशानी के ऑफिस के साथ बच्चों का भी खास ख्याल रख सकती हैं.

ऑफिस गोइंग मदर्स अक्सर घर और काम के बीच में उलझ कर रह जाती हैं. जिसके चलते महिलाएं चिड़चिड़ेपन और तनाव का भी शिकार होने लगती हैं. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं वर्किंग वूमन के लिए कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स, जिसकी मदद से आप ऑफिस में बेस्ट परफॉर्म करने के साथ-साथ परफेक्ट मदर भी बन सकती हैं.

अपना शेड्यूल बनाएं

रोजमर्रा के बिजी लाइफ में वर्किंग वूमन अक्सर ऑफिस और बच्चे से जुड़ी कुछ चीजों को मिस कर देती हैं. ऐसे में आप अपना डेली शेड्यूल प्लान करके सभी चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं. इससे आपको जल्दबाजी में तनाव भी नहीं होगा और आप आसानी से हर काम समय पर खत्म कर पाएंगी.

मल्टीटास्किंग बनें

बच्चे के साथ ऑफिस को मैनेज करने के लिए आप अपने शेड्यूल को मल्टी टास्टिंग भी बना सकती हैं. ऐसे मे किचन का काम करते समय बच्चों का होमवर्क करवाने और डेली वॉक के साथ बिजनेस कॉल अटेंड करके आप टाइम को आसानी से मैनेज कर सकती हैं.

ना कहना सीखें

अच्छी एंप्लॉइ और परफेक्ट मदर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर काम खुद ही करना है. इसलिए ऑफिस में ओवर टाइम करने से लेकर बच्चों के हर काम खुद खत्म करना आपके लिए सही नहीं है. ऐसे में कुछ चीजों के लिए बेझिझक होकर ना कहना भी महिलाओं के लिए जरूरी हो जाता है.

शॉर्टकट होगा बेस्ट

ऑफिस और बच्चे के साथ टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप शॉर्टकट की मदद भी ले सकती हैं. ऐसे में पहले से सब्जी काटकर रखने, डिनर की प्री प्रिपरेशन करने और बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर का इस्तेमाल करके आप घर के कामों को मिनटों में खत्म कर सकती हैं. साथ ही ऑफिस का काम जल्दी खत्म करने के लिए आप बाकी कलीग्स की हेल्प ले सकती हैं.

खुद को समय दें

बच्चे और ऑफिस के साथ-साथ महिलाओं को खुद का भी खास ख्याल रखना चाहिए. ऐसे में आप हर रोज थोड़ा समय खुद के साथ भी बिता सकती हैं. साथ ही हफ्ते में एक दिन अपनी फेवरेट हॉबी फॉलो करके आप लाइफ को फुल एन्जॉय कर सकती हैं.

परिवार में भी महसूस करती हैं अकेलापन, अकेलेपन से बचने के लिए महिलाएं 6 बातों का रखें ख्याल, बेहतर करेंगी महसूस

अगर आप परिवार में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करती हैं या भीड़ में भी कोई अपना नहीं लगता तो यह आपके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है. आइए जानते हैं कि अकेलेपन को आप किस तरह दूर कर सकती हैं.

अकेलेपन की परिभाषा हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकती है. मसलन, कोई अपने रोज के जीवन से उकता जाने की वजह से अकेलापन महसूस करता है तो कोई अपनी बातों को शेयर ना कर पाने की वजह से. कई बार तो लोग भीड़ में रहते हैं, लेकिन उन्हें अपना सा कोई नहीं दिखता और वह अकेली जिंदगी को अपनाना बेहतर समझते हैं. ऐसी परेशानियां आपके सोशल लाइफ को खत्म करने लगती हैं. अगर आप निराश और उदास हैं तो कई बार इस वजह से आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी पैदा होने लगती हैं और लोग निगेटिविटी से बचने के लिए आपसे बात करने से कतराने लगते हैं. यहां हम बात करते हैं कि आप किस तरह अपनी जिंदगी के अकेलेपन को दूर कर सकती हैं और खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरा बना सकती हैं.

खुद के साथ रहें सहज

माइंड वेबसाइट के मुताबिक, कई बार आप अपने साथ बेहतर रिलेशन पैदा कर अकेलेपन को दूर कर सकती हैं. कई महिलाएं सिर्फ इसलिए अकेलापन महसूस करने लगती हैं कि उनका आत्मविश्वास कम हो गया और वह खुद से खुश नहीं हैं. अगर ऐसा है तो खुद को बेहतर लगने वाले काम करें और रोज कुछ नया सीखें.

लोगों से खुलने का करें प्रयास

कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कई लोग हैं लेकिन किसी को भी आपके इमोशन को लेकर फर्क नहीं पड़ता. दरअसल, लोग आपकी परवाह तभी करेंगे, जब आप लोगों के साथ खुलकर बात करेंगी. बेहतर होगा कि आप अपने परिवार या जान पहचान वालों में किसी ऐसे को ढूंढें जिसके साथ खुलकर बात शेयर कर सकें. इस तरह वे आपकी परेशानियों को समझेंगे और आप भी बेहतर महसूस करेंगे.

सोशल बनने का प्रयास

आप अगर लोगों के बीच भी अकेलापन महसूस करती हैं तो बेहतर होगा कि आप सोशल बनने की एक धीमी शुरुआत करें. इसके लिए आप सुबह वॉक पर जाएं तो लोगों को हलो या गुडमॉर्निंग कहें, क्लब ज्वाइन करें, किसी ग्रुप का हिस्सा बनें या महीने में एक बार अपनों से जरूर मिलने के लिए वक्त निकालें.

वॉलेंटियर बनें

अगर आप किसी अच्छे काम में हाथ लगाएंगी तो इससे आपके मन को तसल्ली होगा और आप बेहतर महसूस करेंगी. इसलिए अपने घर के आसपास उन चीजों में वॉलेंटियरिंग करें जिस काम में आपको इंट्रेस्ट रहा हो.

सेल्फ केयर जरूरी

मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए खुद का ख्याल रखना जरूरी है. मसलन आप वॉक पर जाएं, वर्कआउट करें, हेल्दी डाइट लें, मसाल कराएं, स्किन केयर करें, बालों का स्टाइलिंग कराएं या वह सब काम करें जिसे करने के बाद आप बेहतर महसूस करती हैं.

खुद की तुलना दूसरों से ना करें

हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है. ऐसे में लोगों से खुद की तुलना करना बंद कर दें. ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर वक्त लोगों की निगेटिव गौसिप करते हों. अगर आप अपने अंदर की खूबियों को देखें और निगेटिव चीजों को इंप्रूव करने पर ध्यान दें तो आप रोज बेहतर होती जाएंगी और आपका अकेलापन भी दूर होगा.

महिलाओं के लिए संजीवनी हैं ये बीज, अनियमित पीरियड्स जैसी 5 परेशानियों का करते हैं अंत, डॉक्टर से जानें सेवन का तरीका

औषधियों से भरपूर हलीम के बीज महिलाओं की कई परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखते हैं. तमाम पोषक तत्वों से भरपूर लाल रंग के हलीम के बीजों के सेवन से महिलाओं को अनियमित पीरियड्स में सुधार होता है, साथ ही फर्टिलिटी को बढ़ावा मिलता है. आइए आयुर्वेदाचार्य डॉ. विभा वर्मा से जानते हैं हलीम के बीजों से महिलाओं को होने वाले लाभ के बारे में-

आयुर्वेद में कई ऐसे बीजों का जिक्र क्रिया गया है, जो महिलाओं की सेहत के लिए दवा का काम करते हैं. हलीम के बीज इनमें से एक हैं. इन बीजों को चमसूर, चनसूर या गार्डन क्रेस के नाम से भी जाना जाता है. हलीम के इन बीजों को मराठी में अलिव और गुजराती में असेरियो भी कहा जाता है. औषधियों से भरपूर हलीम के बीज महिलाओं की कई परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखते हैं. दरअसल, लाल रंग के हलीम के बीज विटामिन-ए, सी, ई, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, फोलेट और आयरन जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. हलीम के बीजों का सेवन करने से महिलाओं को अनियमित पीरियड्स में सुधार होता है, साथ ही फर्टिलिटी को बढ़ावा मिलता है. आइए यूएचएम हॉस्पिटल कानपुर की आयुर्वेदाचार्य डॉ. विभा वर्मा से जानते हैं हलीम के बीजों से महिलाओं को होने वाले लाभ के बारे में-

हलीम के बीज महिलाओं के लिए कैसे फायदेमंद

पीरियड्स नियंत्रित करें: आयुर्वेदाचार्य डॉ. विभा वर्मा बताती हैं कि, हलीम के बीज का सेवन करने से महिलाओं में अनियमित पीरियड्स की समस्या दूर हो सकती है. बता दें कि, हलीम के बीजों में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं. इसके सेवन से शरीर में हार्मोंस नियंत्रित होते हैं, जिससे अनियमित पीरियड्स की समस्या दूर हो सकती है. इन बीजों को आप दूध में मिलाकर भी सकती हैं।

ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाएं: डॉक्टर के मुताबिक, हलीम के बीज स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. दरअसल, हलीम के बीज का सेवन करने से ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है. ऐसे में डिलीवरी के बाद जिन महिलाओं के स्तनों में ज्यादा दूध नहीं बनता है, वे डॉक्टर की सलाह से हलीम के बीजों का सेवन कर सकती हैं. आप इन बीजों के लड्डू बनाकर भी खा सकती हैं. ऐसा करने से कमजोरी भी दूर हो सकती है.

वजन घटाएं: आयुर्वेदाचार्य बताती हैं कि, वजन घटाने में भी हलीम के बीज कारगर माने जाते हैं. ऐसे में जो महिलाएं अपना वजन घटाना चाहती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है. बता दें कि, हलीम के बीज प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो वजन कम करने में मदद करते हैं. इसके सेवन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती है. ऐसे में, आप ओवरईटिंग से बच सकते हैं.

एनीमिया से राहत: डॉक्टर की मानें तो जिन महिलाओं को एनीमिया की शिकायत हो, उन्हें हलीम के बीज का सेवन जरूर करना चाहिए. दरअसल, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से शरीर में खून बढ़ता है और एनीमिया की शिकायत दूर होती है.

फर्टिलिटी बढ़ाएं: डॉ. विभा वर्मा बताती हैं कि, जो महिलाएं मां बनने की कोशिश कर रही है, उन्हें अपनी डाइट में हलीम के बीज को जरूर शामिल करना चाहिए. यह फॉलिक एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है और फॉलिक एसिड कंसीव करने में मदद करता है।

दिल्ली सरकार ने पानी बर्बादी पर लगाया पहरा पहरा, 200 टीमें तैनात, 2000रू.का जुर्माना

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। दिल्ली में पानी की किल्लत का ठीकरा केजरीवाल सरकार की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा की भाजपा सरकार के सिर फोड दिया है। इधर दिल्ली के प्यासे लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचा रहे है, तो उधर दिल्ली सरकार के जल बोर्ड की 200 टीमों को तैनात कर दिया गया है। ये टीम पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ 2000 रूपये का जुर्माना ठोक देगी। केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नही दे रहा है। उन्होंने धमकी देते हुए यहां तक कह डाला कि यदि आने वाले दिनों में यमुना जल की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के कई इलाके पानी की कमी से जूझ रहे है। ऐसे में उन्होने लोगों को पानी की बर्बादी रोकने की सलाह दी है।अगर पानी की बचत पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया ,तो इसकी निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीम को तैनात किया है जो पानी की बर्बादी करने वालों पर नजर रखेगे। ऐसे लोग जो सीधे जल धारा से गाडी को धोने या टंकी से पानी के ओवर फ्लो करते पाए जाने पर 2000 रूपये का जुर्माना ठोका जाएगा। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि 1मई को वजीराबाद वाटर वर्क में जल स्तर 674.5 फुट था। जबकि पिछले साल अप्रैल, मई और जून में न्यूनतम जल स्तर 674.5 बनाए रखा था। आतिशी ने आंकडे सांझा करते हुए बताया कि 8 मई तक वजीराबाद मे जल स्तर 672 फुट रह गया। वहीं 20 मई तक 671 फुट था। 28 मई को यह घटकर 669.8 फुट रह गया। इसके अलावा जो बोरवेल पहले 6-7 घंटे काम करते थे,वे 14 घंटे काम कर रहे हैं। आतिशी ने बताया कि हमनेञपानी के टैंकर की संख्या भी बढा दी है। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हम उन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कम कर रहे हैं जहां इसकी आपूर्ति दिन में दो बार की जाती थी। वहां अब यह दिन में 1 बार की जाएगी। अब पानी की आपूर्ति तर्क संगत की जाएगी। इस बावत भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के दावे को कोरा झूठ बताया। उन्होने कहा कि हरियाणा ने दिल्ली को पानी की आपूर्ति नियमित जारी की हुई है। उल्टे दिल्ली सरकार पानी की चोरी रोकने में नाकाम रही है।वह जल संकट के लिए जिम्मेदार है।

खराब मौसम बना आफत: आंधी में पेड़ गिरने से दो युवकों की मौत, एक ने मौके पर तो दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। बाहरी-उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में बुधवार शाम आई आंधी के दौरान पेड़ गिरने से अलग-अलग स्कूटी पर सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त पुष्पेंद्र सिंह (23) और विजय (24) के रूप में हुई है। अलीपुर थाना पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। हादसे के समय दोनों युवक पुश्ता रोड से गुजर रहे थे। इस बीच तेज आंधी के दौरान एक बड़ा पेड़ स्कूटी पर गिर गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक स्कूटी के परखच्चे उड़ गए।

दोनों युवक पुश्ता रोड होते हुए हिरंकी चर्च के पास पहुंचे थे कि तेज हवा से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि विजय गंभीर रूप से जख्मी हो गया। राहगीरों ने विजय को नजदीकी बुराड़ी के अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, तेज हवा के साथ बूंदाबांदी, जानें किन इलाकों में बरसेगी 'राहत'

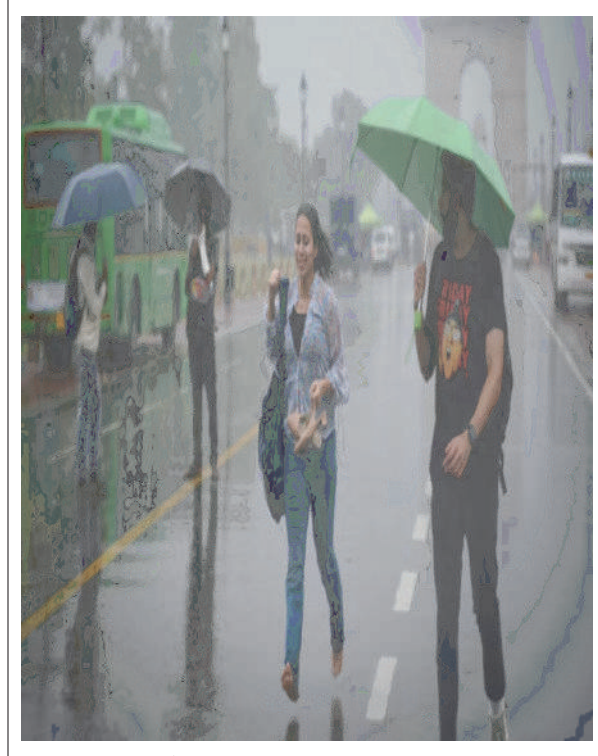

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकर मचा हुआ है। इस बीच बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवा के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बुधवार की शाम होते-होते अचानक मौसम ने करवट बदली। सुबह से तेज धूप रही, लेकिन दोपहर के बाद अचानक अंधेरा छाया और तेज हवा चलने लगी। दिल्ली और इससे सटे नोएडा, गाजियाबाद समेत आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें भी पड़ीं।

बुधवार को हल्की आंधी और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी देर के लिए निजात दिला दी। बीते कई दिनों से गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। शाम के समय मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। तेज हवाएं चलने की वजह से कुछ स्थानों पर पेड़ और होर्डिंग आदि गिर गए।

मर्डर के 11 साल : दिल्ली में हुई मणिपुरी महिला की मौत पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

राजधानी दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 11 साल पहले मणिपुर की महिला की रहस्यमयी मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। चिराग दिल्ली में 2013 में घर के अंदर महिला का शव मिला था।

दिल्ली में 11 साल पहले मणिपुर की महिला की रहस्यमयी मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने सालों पहले अपने घर पर हुई मणिपुर की महिला की रहस्यमयी मौत की जांच अपने हाथ में ले ली है।

जानकारी के लिए बता दें कि 25 साल की एक महिला की दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली में किराए के मकान मौत हो गई थी। 29 मई, 2013 को उसका शव घर में मिला था। शव का चेहरा विकृत और नाक टूटी हुई थी। शव के फर्श पर खून के छींटे मिले थे और खून से लथपथ चादर बरामद हुई थी।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को अपने हाथ में लिया। साथ ही अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एफआईआर को फिर से दर्ज किया है।

भीषण गर्मी के बीच मजदूरों को बड़ी राहत, दोपहर 12 से तीन बजे तक मिलेगी काम से छुट्टी; वेतन भी नहीं कटेगा

नई दिल्ली। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली में उप राज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया है। लेबर और श्रमिकों के लिए दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक काम नहीं करेंगे। इस दौरान उनका वेतन भी नहीं कटेगा। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने यह आदेश जारी किया है।

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने भयंकर गर्मी को देखते हुए मजदूरों के लिए दोपहर 12-3 बजे सवेतन छुट्टी रखने के आदेश दिए हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी 'समर हीट एक्शन प्लान' के लिए अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्रियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने के लिए उप राज्यपाल ने आलोचना की है।

डीडीए 20 मई से ही ऐसा कर रहा है, पर आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत आने वाली दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी अब तक ऐसा नहीं कर रहीं थीं। इस संबंध में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को तत्काल बैठक करने का निर्देश जारी किया है।

इसके साथ ही उप राज्यपाल ने निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी उप्लब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने के निर्देश दिए हैं।

अभी दो दिन नहीं मिलेगी लू से राहत : दिल्ली में गर्मी और हीट वेव जारी है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी के तीन केंद्रों पर तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच गया। मुंगेशपुर व नरेला में अधिकतम तापमान 49.9 व नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कहा कि अभी कम से कम दो दिन प्रचंड गर्मी और लू से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है।

दिल्ली की गर्मी, सावधानी ही सुरक्षा !

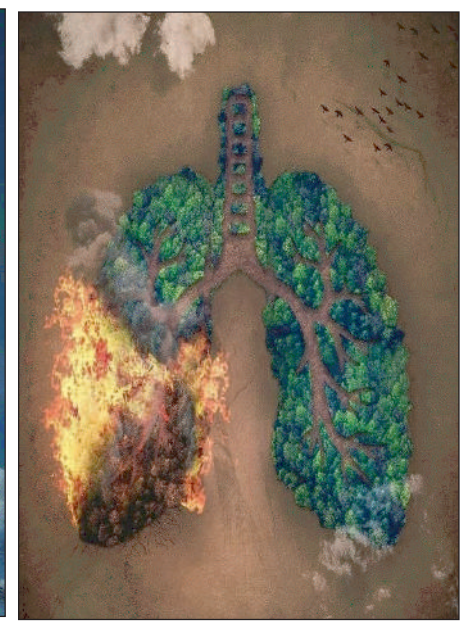

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में 50 डिग्री+ तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे उच्चतम तापमान है। इस अत्यधिक गर्मी में सड़क पर यात्रा करते समय या ड्राइविंग करते समय खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावः

पानी का सेवन: अपने साथ पर्याप्त पानी रखें और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय भी लाभदायक होते हैं।

हल्के और ढीले कपड़े पहनें: सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें जो पसीना सोख सकें और शरीर को ठंडा रखें। सिर को ढकने के लिए टोपी या स्कार्फ का उपयोग करें।

सनस्क्रीन का उपयोग करें: अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए उच्च एसपीएफ वाली सनस्क्रीन का प्रयोग करें। इसे यात्रा शुरू करने से 20 मिनट पहले लगाएं और हर 2 घंटे बाद पुनः लगाएं।

गाड़ी की तैयारी: अपनी गाड़ी के एयर कंडीशनर को ठीक से काम करने की स्थिति में रखें। विंडशील्ड पर सनशेड का इस्तेमाल करें और कार को छांव में पार्क करने की कोशिश करें।

यात्रा का समय चुनें: जब संभव हो, सुबह जल्दी या शाम को देर से यात्रा करें। इस समय तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है।

ठंडी तौलिया या वाइप्स रखें: चेहरे और गर्दन को ठंडा रखने के लिए ठंडी तौलिया या वाइप्स का उपयोग करें।

आवश्यक ब्रेक लें: अगर आप लंबी यात्रा पर हैं, तो नियमित अंतराल पर ब्रेक लें और किसी ठंडी जगह पर आराम करें।

आपातकालीन किट रखें: अपने वाहन में एक आपातकालीन किट रखें जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, अतिरिक्त पानी, और कुछ स्नैक्स शामिल हों।

भीड़भाड़ से बचें: ट्रैफिक जाम में फंसने से बचें, जिससे गर्मी के प्रभाव को और भी ज्यादा महसूस ना करना पड़े।

ध्यान केंद्रित रखें: अत्यधिक गर्मी के कारण ध्यान भटक सकता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय पूर्ण सतर्कता बरतें।

इस प्रकार की तीव्र गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें और गर्मी से संबंधित किसी भी समस्या पर तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

डॉ अंकुर शरण, राष्ट्रीय मुख्य परिवहन एवं योजना अधिकारी
Road Safety Omni Foundation
roadsafetysquad@gmail.com

दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान

परिवहन विशेष न्यूज

मौसम विभाग ने पहले ही बुधवार (29 मई) को गर्मी व लू का रेड अलर्ट जारी किया था।मंगलवार यानी कल मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था।

नई दिल्ली। दिल्ली में इन दिनों गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बुधवार को राजधानी का मुंगेशपुर इलाका सबसे गर्म रहा। यहां 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। जबकि मंगलवार यानी कल मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने पहले ही बुधवार (29 मई) को गर्मी व लू का रेड अलर्ट जारी किया था।

आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मुंगेशपुर मौसम केंद्र में उच्चतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को नजफगढ़ में 48.6 डिग्री सेल्सियस, जफरपुर में 48 डिग्री, पूसा में 48.3 डिग्री, नरेसा में 47.9 डिग्री और पीतमपुरा में 48.3 डिग्री सेल्सियस तामपान रहा।

दिल्ली का 10 साल में 7 डिग्री बढ़ा तापमान

दिल्ली गर्म द्वीपों का शहर बन गई है। बीते एक दशक में राजधानी के तापमान में औसतन सात डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 की मई में अमूमन 30-33 डिग्री तक गर्म रहने वाली दिल्ली 2024 की मई में 40 डिग्री तक गर्म है। मौसम विभाग अभी राहत की भी कोई खबर नहीं दे रहा है। पूर्वानुमान है कि जून के पहले सप्ताह तक दिल्ली 40 डिग्री से ऊपर की तपिश झेलती रहेगी। इसके बाद ही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने दिल्ली के मई महीने के तापमान पर शोध किया है। इससे पता चलता है कि मई 2014 में दिल्ली का औसत तापमान 30-33 डिग्री सेल्सियस के बीच था। कुछ ही इलाके ऐसे थे, जहां का तापमान 33.1-34 डिग्री सेल्सियस रहा। इसमें भी ज्यादातर इलाके उत्तरी व दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के बाहरी इलाके थे। इसके उलट 2022 में दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। पूर्वी व मध्य दिल्ली के चंद इलाके ही 36-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे।

सेटेलाइट डाटा के आधार पर की गई मैपिंग से पता चलता है कि दिल्ली के औसत तापमान में बढ़ोतरी की शुरुआत 1998 से हो रही है। लेकिन, 2014 के बाद से इसमें तेजी से इजाफा हुआ है। एक दशक के तापमान में सात डिग्री का फर्क आ गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्म द्वीप स्थानीय मौसम पर सीधा असर डाल रहे हैं। गर्म इलाकों में अपेक्षाकृत बारिश कम होती है, जबकि हरे-भरे इलाकों में ज्यादा। इसकी वजह यह है कि हरे क्षेत्र हवा की नमी खींच लेते हैं। जबकि कंक्रीट वाले इलाकों की हवा पूरी तरह शुष्क रहती है। इस बार दिल्ली में इसी तरह की बारिश हुई।

दिन में ग्रामीण क्षेत्र गर्म

नजफगढ़, मुंगेशपुर, जाफरपुर सरीखे बाहरी दिल्ली के इलाकों में ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हो रहा है। वह इसलिए कि इस वक्त फसलें कट गई हैं। तुलनात्मक रूप से हरियाली नहीं रहती। सघन आबादी वाले यह इलाके पथरीले भी हैं। इसके मिले-जुले असर से यहां का तापमान बाकी दिल्ली से ज्यादा है।

बड़ी वजहें

. इसकी बड़ी वजह निर्माण स्थलों में बढ़ोतरी है। 2003 में दिल्ली का 31.4 फीसदी क्षेत्र निर्मित था। 2022 में यह 38.2 फीसदी पहुंच गया। इससे बचने के लिए हरियाली बढ़ानी पड़ेगी। इसमें वही पौधे लगाए जाएं, जो दिल्ली की आबोहवा के हिसाब से हों। खेतिहर इलाकों में ज्यादा समय पर हरी-भरी हरने वाली फसलों को लगाया जाए।

. घनी बसावट, वाहनों की संख्या ज्यादा।

. आवासीय व व्यावसायिक परिसरों की संख्या बढ़ने से बढ़ा तापमान।

. प्रदूषक की मात्रा बढ़ने के साथ जमीन के नजदीक ओजोन का स्तर भी बढ़ा। दोनों ने मिलकर बढ़ाई गर्मी।

शहरी गर्म द्वीप

शहरों के बीच बसे ऐसे इलाके, जहां का औसत सालाना तापमान अपने आसपास के क्षेत्रों से ज्यादा दर्ज होता है उन्हें गर्म द्वीप माना जाता है। शोध के मुताबिक दिल्ली में संगम विहार, बदरपुर, जैतपुर, आईजीआई एयरपोर्ट, नजफगढ़, छतरपुर, मुंडका, जाफरपुर, मुंगेशपुर, नरेला, शाहदरा सरीखे इलाके इसी श्रेणी में आते हैं।

इस तरह बढ़े गर्म द्वीप

2014: उत्तरी दिल्ली का बवाना।

2016: नजफगढ़, रोहिणी, राजौरी गार्डन, नरेला समेत दूसरे इलाके।

2018: संगम विहार, बदरपुर, जैतपुर, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट।

2022: जाफरपुर, छतरपुर, मुंगेशपुर, मुंडका, शाहदरा।

2024: लोधी रोड, रिज, पूसा, राजघाट।

बढ़ते तापमान का असर

.पानी की गुणवत्ता होती है प्रभावित।

.ऊर्जा की मांग में इजाफा, एसी, फ्रिज ज्यादा चलने से बढ़ता है वायु प्रदूषण।

.बच्चों और बुजुर्गों में दिल व सांस से जुड़ी बीमारियों की बढ़ जाती है आशंका।

.सुबह और शाम का तापमान होता है ज्यादा।

विशेषज्ञ की रायः

बढ़ती गर्मी से दिन व रात और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान में देखा जा सकता है। बीते एक दशक में रातों की गर्मी नौ फीसदी से बढ़ी है। वहीं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के तापमान में 3.8 फीसदी का फर्क है। रात को ग्रामीण इलाके 12.2 डिग्री ही ठंडे हो जाते हैं। जबकि शहर का केंद्र केवल 8.5 डिग्री ठंडा होता है। -शरणजीत कौर, कार्यक्रम अधिकारी, सीएसई

गर्म द्वीप का सबसे अधिक असर रात के तापमान में देखा जाता है। अगर रात भर तापमान अधिक रहता है तो लोगों को दिन की गर्मी से उबरने का मौका कम मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण जमीन को इस्तेमाल करने का तरीका बदल रहा है। अधिक से अधिक कंक्रीट का जाल बिछाया जा रहा है। इससे सूर्य की किरणों को अधिक फैलाव नहीं मिलता है, जिससे उस क्षेत्र में अधिक गर्मी होती है। यही नहीं, तेजी से जलाशय कम या खत्म हो रहे हैं। ऐसे में गर्म द्वीप बढ़ रहे हैं। गर्मी और उमस से लोग पहले से अधिक परेशान हो रहे हैं।

-प्रसून सिंह, फेलो, टीईआरआई

नोएडा में अमिताभ कांत की सिफारिश को बिल्डरों ने किया स्वीकार, रियल एस्टेट सेक्टर में आया बूम

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को बिल्डरों ने स्वीकार कर लिया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से तेजी बढ़ी है। प्राधिकरण में सिफारिश लागू होने के बाद बिल्डर व खरीदारों के बीच करीब 95 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो गया है। 90 प्रतिशत बिल्डरों ने प्राधिकरण में 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है। रेडी टू मूव के साथ अब रजिस्ट्री वाले घर नया बेंचमार्क बन चुका है।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। जो लोग अपने लिए नोएडा- ग्रेटर नोएडा में दो या तीन बीएचके फ्लैट देख रहे थे। लोकेशन पसंद कीमत भी जद में थी, लेकिन फ्लैट की रजिस्ट्री बंद होने की वजह से खरीदारी नहीं कर रहे थे। उन खरीदारों की जेब पर अचानक आर्थिक बोझ बढ़ गया है, क्योंकि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को बिल्डरों ने स्वीकार कर लिया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से तेजी बढ़ी है।

90 प्रतिशत बिल्डरों ने जमा कर दी 25 प्रतिशत धनराशि

बता दें कि प्राधिकरण में सिफारिश लागू होने के बाद बिल्डर व खरीदारों के बीच करीब 95 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो गया है। 90 प्रतिशत बिल्डरों ने प्राधिकरण में 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है। चरणबद्ध रूप में रजिस्ट्री करानी शुरू कर दी है।

इससे गौतमबुद्धनगर में प्रोमोटर्स की अलग-अलग परियोजनाओं में नोएडा में 12 हजार रजिस्ट्री का रास्ता खुला है। इसमें 1200 रजिस्ट्री अब तक हो चुकी। ग्रेटर नोएडा में 50 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री की अनुमति प्राधिकरण से बिल्डरों को मिल चुकी है, जिसमें 14 हजार के करीब रजिस्ट्री शुरू कराई जा चुकी है।

रेडी टू मूव के साथ अब रजिस्ट्री वाले घर नया बेंचमार्क बन चुका है, जो निवेश को सुरक्षित बना रहा है। बता दें कि घर खरीदार भी केवल रजिस्ट्री होने वाले फ्लैट और सोसायटी में ही घर लेना चाहते है, लेकिन बाजार में दो व तीन बीएचके यूनिट्स रेडी टू मूव गिने-चुने बचे हैं।

बिल्डरों की रजिस्ट्री खुलने से बढ़े प्रॉपर्टी के रेट

बिल्डर रजिस्ट्री वाले फ्लैट्स की कीमत में पहले से औसतन 30-40 प्रतिशत की वृद्धि करके बिक्री कर रहे थे, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन कुछ सेक्टरों में फंसी बिल्डरों की रजिस्ट्री खुलने से अचानक प्रॉपर्टी के रेट एक साल के अंदर दो से तीन गुना तक बढ़ चुके है।

क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के सचिव दिनेश गुप्ता ने बताया कि रजिस्ट्री होने से अब खरीदार भी अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकेंगे, जो पहले संभव नही था। यह पूरे सेक्टर के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत है। बाजार पूरी तरीके से मांग सप्लाई पर टिका है।

घर खरीदार भी अब पहले से ज्यादा

जागरूक है। कब्जा सहित रजिस्ट्री वाले घरों को प्राथमिकता दे रहे है। रजिस्ट्री खुलने के कुछ दूरगामी प्रभाव भी अभी से दिखने लगे है।

स्पोर्ट्स सिटी को छोड़ सभी सोसायटी में हो सकती रजिस्ट्री

यदि स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाओं को छोड़ दे तो पूरे गौतमबुद्ध नगर के हाउसिंग सोसायटी में रजिस्ट्री कराई जा सकती है। ऐसे में कुछ बिल्डर अब अपनी पुरानी परियोजनाओं की शेष भूखंड पर नए टावर लाने की योजना भी बना रहे है।

कुछ बिल्डर ऐसे भी है जो पूर्व निर्मित परियोजनाओं में शेष निर्माण और विकास कार्यों को जल्दी से पूरा करके ओसी / सीसी के साथ बची हुई यूनिटस अच्छे रेट में बेचने की तैयारी में है। आरजी ग्रुप, एक्सप्रेस ग्रुप, इरोज ग्रुप सहित ऐसे कई बिल्डर्स है जो शेष भूखंड पर सीमित टावर का निर्माण करने जा रहे है।

खरीदारों ने सुविधाओं के आगे खर्च को पीछे छोड़ा

खरीदार अब अब भव्य प्रवेश द्वारों, शानदार सुविधाओं वाले क्लब हाउस, बढ़िया लैंडस्केपिंग, गेमिंग, स्पोर्ट्स, मनोरंजन क्षेत्र और यहां तक कि आने वाले मेहमानों के लिए आंतरिक सुविधाओं के बारे में भी सोच रहे है। इसलिए इन सुविधाओं पर ग्राहकों की ओर से खर्च करने से परहेज नहीं किया जा रहा हे।

महिला के साथ मारपीट करने से रोका तो सिर में हथौड़ा मार कर दी हत्या, आरोपित गिरफ्तार

गाजियाबाद। महिला से मारपीट करने से रोकने पर उसके पति ने युवक की सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया है। डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित रोहित शर्मा निठोरा रोड स्थित डायमंड सिटी का रहने वाला है।

वह 27 मई की रात को पत्नी पूनम के साथ मारपीट कर रहा था। बचाव के लिए महिला मकान के पास ही स्थित ऑफिस में काम करने वाले गढ़ी जस्सी के संदीप कुमार, अशोक विहार के राजू उर्फ राज शर्मा के पास मदद मांगने पहुंची।

उसका पीछा करते हुए रोहित भी वहां पहुंच गया और डंडे से पत्नी पर वार करने का प्रयास किया तो संदीप और राजू ने डंडा छीन लिया और धक्का देकर रोहित को गिरा दिया। इसके बाद रोहित वहां से चला गया और घर से हथौड़ा लेकर संदीप और रोहित पर हमला करने के लिए आया। तब तक संदीप जा चुका था और राजू पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था, रोहित ने पीछे से राजू के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। शव को कच्चे रास्ते के किनारे फेंककर वहां से भाग गया। 28 मई की सुबह शव मिलने पर पुलिस (Ghaziabad Police) ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान हत्या की वारदात में रोहित का नाम सामने आया तो उसे बुधवार को अशोक विहार से गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद किया गया है।

नोएडा में गुपचुप दे दिए पिंक ऑटो के 160 परमिट, व्यवस्था पर उठे सवाल

परिवहन विशेष न्यूज

गुपचुप दे दिए 160 परमिट व्यवडीलर 2.73 लाख के ऑन रोड पिंक ऑटो को 4.50 लाख रुपये में परमिट समेत बेच रहा है जबकि जानकारी नहीं होने के कारण आम और जरूरतमंद महिला चालकों को परमिट नहीं मिल सके। यूनियन अध्यक्ष ने पिंक ऑटो के परमिट ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर और वीडियोग्राफी कराकर दिए जाने की मांग की है।

नोएडा। दिल्ली एनसीआर में ऑटो परमिट मिलने की रोक के आड़ में पिंक ऑटो के 160 परमिट गुपचुप तरीके से दे दिए गए। अब डीलर 2.73 लाख के ऑन रोड पिंक ऑटो को 4.50 लाख रुपये में परमिट समेत बेच रहा है जबकि जानकारी नहीं होने के कारण आम और जरूरतमंद महिला चालकों को परमिट नहीं मिल सके।

नोएडा ऑटो चालक रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने इस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए हैं। सभी परमिट डीलरों को देने का आरोप लगाया है। एआरटीओ नोएडा को मंगलवार को पत्र सौंपकर और आरटीओ गाजियाबाद को पत्र लिखकर शिकायत की है।

बिना सूचना दिए जारी कर दिए पिंक ऑटो का परमिट

नोएडा ऑटो चालक रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष लाल बाबू ने बताया कि वर्ष 2015 में परिवहन विभाग की ओर से एक हजार ऑटो एनसीआर में चलवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरवाए गए थे। चालक ऑटो पाने के लिए पंजीकरण कराकर निर्धारित शुल्क जमा करा चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑटो नहीं मिल पाए हैं।

अब 2021 के बचे हुए पिंक ऑटो का परमिट बिना सूचना दिए जारी कर दिए। इसके लिए कोई आनलाइन प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। आरटीओ गाजियाबाद की ओर से चुनिंदा ऑटो डीलरों को सेक्शन लेटर दिए गए हैं। इसी सेक्शन लेटर के माध्यम से डीलर डीलर 2.75 लाख के पिंक ऑटो को 4.50 लाख रुपये में बुक कर रहा है।

नोएडा के एक डीलर को दिए 90 परमिट

यूनियन अध्यक्ष लाल बाबू का आरोप है कि आरटीओ गाजियाबाद की ओर से नोएडा के एक बड़े डीलर को 90 परमिट दिए गए हैं। डीलर की सेक्टर 49 और सेक्टर पांच हरौला में एजेंसी है जबकि 160 में से अन्य डीलरों को 30, 20 व दस परमिट दिए गए हैं।

इससे कई वर्षों से पिंक ऑटो चलाने की चाहत लिए बैठीं महिला चालकों धक्का लगा है। अब उनको बाजार कीमत से 1.85 लाख रुपये ज्यादा देकर पिंक ऑटो खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। उधर, यूनियन अध्यक्ष ने पिंक ऑटो के परमिट ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर और वीडियोग्राफी कराकर दिए जाने की मांग की है।

क्या बोले जिम्मेदार

एआरटीओ नोएडा डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि पिंक ऑटो के परमिट मिलने पर किसी तरह की रोक नहीं है। इसको लेने के लिए महिला का खुद आवेदक, चालक व महिलाओं के लिए चलाने की तीन शर्त का पालन करना जरूरी है। यूनियन के लगाए सभी आरोप निराधार हैं। उधर, आरटीओ पीके सिंह का मोबाइल नंबर बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो सका।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी सीटों पर जीत का भरा दम, BJP-JJP को लेकर कही ये बात

प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब सभी दलों को 4 जून का इंतजार है। इस दिन वोटों की गिनती होनी है लेकिन उससे पहले अब भाजपा-कांग्रेस ने सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि दस की दस सीटें कांग्रेस जीतेगी। जबकि इससे पहले बीते दिन पूर्व सीएम मनोहर ने जीत का दम भरा था।

गुरुग्राम। (Gurugram Hindi News) गुरुग्राम के कमान सराय स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस दस की दस सीटें जीतेगी। प्रदेश में अब शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है।

अब ईमानदारी से मतगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर पहली बार हुआ है कि वोटिंग के कई दिन बाद छह प्रतिशत वोट बढ़ गए।

87 का सदन, 44 विधायकों से चला रहे सरकार-उदयभान

प्रदेश अध्यक्ष (Chaudhary Udaybhan) ने कहा प्रदेश में भाजपा सरकार (Haryana BJP) अल्पमत में है, यह सबको पता है। 87 का सदन है। भाजपा को 44 विधायक चाहिए। इन्हें सिर्फ 42 का ही समर्थन प्राप्त है। 45 विधायक विपक्ष में हैं। भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए अधिकार नहीं है।

भाजपा, जेजेपी के विधायकों को तोड़ने की कर रही कोशिश-कांग्रेस

सरकार को विश्वास मत हासिल करना चाहिए। उदयभान भाजपा (Haryana BJP) पर विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। भाजपा, जेजेपी (JJP News) के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

मीडिया: दरकते भरोसे को बचाएं कैसे

- प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है, तो वह अकारण नहीं है। उसने समय-समय पर लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए बहुत काम किया है और इसके लिए बड़ी कीमत भी चुकाई है।

हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते समय हम सवालों से घिरे हैं और जवाब नदारद हैं। पं.जुगुलकिशोर शुकुल ने जब 30 मई ,1826 को कोलकाता से उदंत मार्तण्ड की शुरुआत की तो अपने प्रथम संपादकीय में अपनी पत्रकारिता का उद्देश्य लिखते हुए शीर्षक दिया - 'हिंदुस्तानियों के हित के हेत'। यही हमारी पत्रकारिता का मूल्य हमारे पुरखों ने तय किया था। आखिर क्यों हम पर इन दिनों सवालिया निशान लग रहे हैं। हम भटके हैं या समाज बदल गया है?

कुछ दिनों पहले दिनों, देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि किसी देश को लोकतांत्रिक रहना है, तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए। जब प्रेस को काम करने से रोका जाता है, तो लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता होता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश, ऐसा कहने वाली पहली विभूति नहीं हैं। उनसे पहले भी कई बार कई प्रमुख हस्तियां प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर मिलते-जुलते विचार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर चुकी हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है, तो वह अकारण नहीं है। उसने समय-समय पर लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए बहुत काम किया है और इसके लिए बड़ी कीमत भी चुकाई है। इसके बदले उसे समाज का, लोगों का भरपूर विश्वास और सम्मान भी हासिल हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से बीते दो-तीन दशकों में यह विश्वास लगातार दरकता गया है, सम्मान घटता गया है।

मीडिया की इस घटती प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के पीछे बहुत सारे कारण गिनाये जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि उदारीकरण की आंधी से पहले जिस मीडिया ने खुद को एक मिशन बनाए रखा था, उसने व्यावसायिकता की चकाचौंध में बहुत तेजी से अपना 'कॉरपोरेटाइजेशन' कर लिया और खुद को 'मिशन' की बजाए खालिस 'प्रोफेशन' बना लिया। अब जब यह प्रोफेशन बना तो इसकी प्राथमिकताएं भी बदल गईं। 'जन' की जगह 'धन' साध्य बन गया। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मीडिया प्रतिष्ठानों ने अपने तौर-तरीके पूरी तरह बदल लिए। 'कंटेंट' की बजाय उन्होंने 'आइटम' पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि रीडरशिप और टीआरपी में ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा जा सके। जितनी ज्यादा ऊंचाई, उतना ज्यादा विज्ञापन राजस्व। उसमें भी भारी घालमेल। अधिकतर अखबार और टीवी चैनल, सामग्री की गुणवत्ता की बजाए आंकड़ों की बाजीगरी में अधिक भरोसा करने लगे। लेकिन, या तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर परवाह नहीं की, कि इस पूरे चक्र में वे समाज और लोगों का भरोसा खो रहे हैं।

अब स्थिति यह है कि मीडिया तो लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन लोगों में उसकी विश्वसनीयता लगातार कम हो रही है। आज मीडिया के बहुत सारे रूप हैं। मनोरंजन को छोड़ दीजिए, तो रेडियो ज्यादा लोग सुनते नहीं, टीवी देखते नहीं, अखबार पढ़ते नहीं' अगर यह सब करते भी हैं, तो ये माध्यम उनके मन में कोई सकारात्मकता जगा पाने में सफल नहीं हो पाते। जबकि कालांतर में ऐसे असंख्य अवसर आए हैं, जब मीडिया ने अपने सामाजिक और लोकतांत्रिक दायित्वों का भली-भांति निर्वहन किया है। विश्वसनीयता के मामले में पत्रकारिता को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, 21 वीं सदी के आरंभ से पहले की पत्रकारिता और दूसरी इसके बाद की पत्रकारिता। पहले वर्ग में वह पत्रकारिता आती है जो समाज के लिए जयप्रकाश नारायण और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नायकों को मजबूती प्रदान करती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती थी, जनहित के लिए सत्ता की नाक में दम किए रहती थी। दूसरी पत्रकारिता वर्ष 2000 से बाद की पत्रकारिता है, जिसमें सनसनी है, स्टिंग हैं, मीडिया ट्रायल हैं, टीआरपी है, प्रायोजित यात्राएं हैं, निहित स्वार्थ हैं। अगर कुछ नहीं है, तो समाज का विश्वास। अब कोई मीडिया की ओर नहीं देखता। लोग उससे कोई उम्मीद नहीं रखते, उस पर भरोसा नहीं करते। उनके लिए मीडिया पर प्रसारित सामग्री मनोरंजन की चीज बन चुकी है। हालांकि अखबार अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ इसी राह पर रहे हैं।

इसकी दूसरी वजह पिछले दस-पंद्रह सालों में वैकल्पिक मीडिया, या डिजिटल मीडिया, का दिनोंदिन फैलता फलक हो सकती है। वैकल्पिक मीडिया ने, आम लोगों को अपनी बात सामने रखने की ऐसी सहूलियत प्रदान की है, जिसने पारंपरिक संचार माध्यमों पर उनकी निर्भरता खत्म कर दी है। अब वे अपनी समस्याएं या चिंताएं लेकर अखबारों-टीवी चैनलों के चक्कर नहीं काटते, बल्कि फेसबुक या ट्विटर पर पोस्ट करते हैं। क्योंकि इनमें उन्हें भरोसा रहता है कि अब उनकी बात बिना किसी बाधा या समस्या के उन तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी, जिन तक पहुंचनी चाहिए। तीसरी वजह, खुद वह समाज है जो मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने का दोषारोपण तो करता है, लेकिन कभी किसी संकट के समय उसके साथ खड़ा नजर नहीं आता। 'रिपोर्टर विदआउट बॉर्डर्स' के मुताबिक वर्ष 2003 से 2022

तक, दो दशकों के दौरान दुनिया भर में 1668 पत्रकारों की हत्या हुई। यानि हर साल करीब 84 पत्रकार। इसके अलावा 'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल एक दिसंबर तक 363 पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। 'रिपोर्टर विदआउट बॉर्डर्स' की रिपोर्ट इनकी संख्या 533 बताती है। उनकी ताजा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में पिछले साल 65 पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को बंधक बनाकर रखा गया और 49 लापता हैं।

अब आप याद कीजिए कि क्या कहीं आपने किसी देश, शहर या समाज में लोगों को इस बात के लिए इकट्ठा होकर कोई सामाजिक आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते देखा है कि अमुक पत्रकार को जेल से रिहा किया जाए, या अमुक पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए या अमुक पत्रकार, जिसका अर्से से कोई अता-पता नहीं है, उसका पता लगाया जाए। और तो और, जिन लोगों के हित के लिए पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डाली है, समाज उनके परिवार की मदद के लिए भी कभी खड़ा नजर नहीं आता। वही समाज जो पानी न आने पर सड़कें जाम कर देता है, किसी सैनिक के शहीद होने पर श्रद्धांजलि यात्राएं निकालता है। अपने अधिकारों के लिए या अपने शहीदों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर आना कतई गलत नहीं है और न ही यहां इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि कहने का आशय यह है कि एक पत्रकार जब अपना फर्ज निभाते हुए मारा जाता है तो उसकी शहादत, उस समाज से भी बदले में कुछ चाहती है, जिसके लिए वह शहादत दी गई। बजाय इसके, हम उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं या उस पर हमले को जायज साबित करने की कोशिश करते हैं। कहने का आशय यह है कि अगर मीडिया और समाज के बीच विश्वास मिट रहा है, तो इसके लिए अकेले मीडिया को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आखिर मीडिया भी तो हमारे समाज का ही एक हिस्सा है, जैसा समाज हमने बीते कुछ दशकों में बनाया है, उसका असर मीडिया पर न पड़े, यह कैसे मुमकिन है।

इसलिए अगर मीडिया के प्रति लोगों में, समाज में, विश्वास की पुनर्बहाली करनी है, तो दोनों स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती।

जल्द आ सकती है फेम-3 स्कीम, Electric के साथ शामिल हो सकते हैं हाइब्रिड वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई Fame Subsidy Scheme के तीसरे चरण को जल्द लाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Fame-3 स्कीम को कब लाया जा सकता है और क्या इसमें Electric के साथ ही Hybrid वाहन भी शामिल हो सकते हैं। आइए जानते हैं।

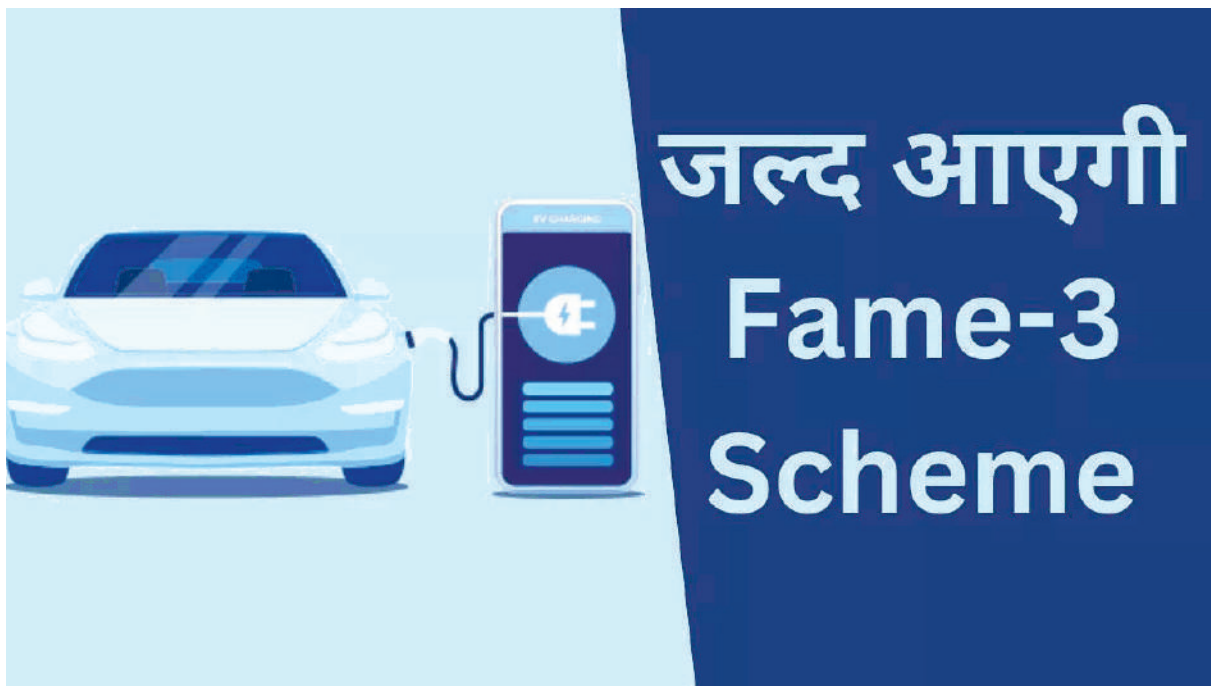

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल इंजन वाले वाहनों के मुकाबले Electric Vehicle को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से Fame-3 स्कीम को जल्द लाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से इसे कब तक पेश किया जा सकता है और क्या इसमें Hybrid वाहनों को भी शामिल किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

आएगी Fame-3 Scheme

केंद्र सरकार की ओर से Electric Vehicle को बढ़ावा देने के लिए Fame-3 Scheme को जल्द पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद अगले 100 दिनों में इस स्कीम को पेश किया जा सकता है। जिसमें सरकार वाहनों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का आउटले जारी कर सकती है।

कौन से वाहन होंगे शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से लाई जाने वाली फेम-3 स्कीम में इलेक्ट्रिक दो पहिया के साथ ही तिपहिया और सरकारी बसों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक कारों और हाइब्रिड तकनीक वाली कारों को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस स्कीम में 15 लाख रुपये तक की कारों को ही शामिल करने की संभावना ज्यादा है।

फिलहाल मिल रही EMPS स्कीम से सब्सिडी

केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल EMPS स्कीम के जरिए इलेक्ट्रिक दो पहिया और तीन पहिया वाहनों पर सब्सिडी को दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक दो पहिया पर अधिकतम 10-11 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। वहीं तीन पहिया वाहनों पर करीब 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी को दिया जा रहा है।

March 2024 तक मिलती थी ज्यादा सब्सिडी

सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए साल 2015 में Fame सब्सिडी के पहले चरण को शुरू किया था। एक अप्रैल 2015 से लागू हुई इस स्कीम को पहले दो साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन लोगों की रूचि बढ़ने के कारण इसे 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया था। इस दौरान करीब 529 करोड़ रुपये के फंड को दिया गया था। इसके बाद एक अप्रैल 2019 से Fame-2 सब्सिडी को लागू किया गया था, जिसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। इस दौरान भी लोगों ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदा था। लेकिन एक अप्रैल 2024 से सरकार ने EMPS को लागू किया था, जो सिर्फ चार महीनों के लिए लाई स्कीम थी। मार्च 2024 तक सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कारों को भी सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन एक अप्रैल 2024 से लागू हुई EMPS को सिर्फ दो पहिया, तीन पहिया को ही सब्सिडी दी जा रही थी। इस सब्सिडी को भी सरकार ने Fame-1 और Fame-2 के मुकाबले काफी कम कर दिया था।

एमजी मोटर और HPCL मिलकर चार्ज करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल पंप पर फास्ट चार्जर लगाने की तैयारी

नई दिल्ली। MG Motor India ने बुधवार को कहा कि उसने देशभर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के साथ हाथ मिलाया है।

MG लगाएगी नए EV Charger

ऑटोमेकर ने एक बयान में कहा कि सहयोग के अनुसार, एमजी और एचपीसीएल मिलकर भारत भर के राजमार्गों और शहरों को कवर करने वाले प्रमुख स्थानों पर 50kW/60kW डीसी फास्ट चार्जर लगाएंगे। इसमें कहा गया है कि यह साझेदारी ईवी उपयोगकर्ताओं को उनकी लंबी दूरी और इंटर-सिटी यात्राओं के दौरान ईवी चार्जर की उपलब्धता बढ़ाकर सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।

HPCL के पास 22 हजार से ज्यादा फ्यूल स्टेशन

एचपीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक - हाईवे रिटेलिंग राजदीप घोष ने कहा कि कंपनी के पास 22,000 से अधिक फ्यूल स्टेशनों का देशव्यापी नेटवर्क है और वह ग्राहकों को ग्रीन फ्यूल प्रदान करके एक स्थायी भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद घर लाएं मारुती की 7 सीटर ईको CNG, जानें कितनी देनी होगी EMI

मारुति की ओर से बजट सेगमेंट में Eeco CNG को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस कार को देश में बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके CNG वेरिएंट को एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद कितने साल की EMI पर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता की ओर से Eeco को सात सीटों वाली गाड़ी के तौर पर भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। हर महीने बड़ी संख्या में लोग इस कार को खरीदते हैं। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितनी है कीमत

मारुति की ओर से Eeco के CNG वेरिएंट को 6.58 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। इसे दिल्ली में खरीदने पर कुल 7.58 लाख रुपये देने होंगे। इस कीमत में 6.58 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के अलावा 46890 रुपये आरटीओ और 48359 रुपये का इंश्योरेंस और 5485 रुपये फास्टैग, स्मार्ट कार्ड सहित कुछ एक्सेसरीज भी शामिल है।

एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर इस गाड़ी के CNG वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.58 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 8.7 फीसदी ब्याज के साथ छह साल के लिए 6.58 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11763 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार

अगर आप 8.7 फीसदी की ब्याज दर के साथ छह साल के लिए 6.58 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको छह साल तक 11763 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में छह साल में आप Eeco के लिए करीब 1.89 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 9.47 लाख रुपये देंगे।

Audi Q6 e-tron को मिला RWD वेरिएंट, प्रीमियम फीचर्स के साथ सिंगल चार्ज पर मिलेगी इतनी रेंज

Audi Q6 e-tron को RWD वेरिएंट मिला है। Q6 ई-ट्रॉन पोर्श मैकन EV के साथ अपनी अंडरपिनिंग साझा करती है जो कंपनी के लिए इस प्लेटफॉर्म का पहला उपयोग है। इस नए मॉडल में अधिकतम 240 kW का आउटपुट है और यह 100 kWh की हाई-वोल्टेज बैटरी से लैस है। WLTP के अनुसार ऑडी Q6 ई-ट्रॉन 641 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज प्रदान कर सकती है।

नई दिल्ली। Audi ने अपनी Q6 e-tron का नया रियर-व्हील ड्राइव (RWD) वेरिएंट पेश किया है। ऑडी का दावा है कि यह अत्यधिक एफिशियंट है, जो इस ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी की लाइनअप का और विस्तार करता है।

Audi Q6 e-tron में क्या खास?

Audi Q6 ई-ट्रॉन पोर्श मैकन EV के साथ अपनी अंडरपिनिंग साझा करती है, जो कंपनी के लिए इस प्लेटफॉर्म का पहला उपयोग है। PPE नामक ये आर्किटेक्चर 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम का उपयोग करता है और इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं।

डायमेंशन की बात करें, तो ये 4771 मिमी की लंबाई, 1993 मिमी की चौड़ाई और 1648 मिमी की ऊंचाई के साथ पिछली सीट पर भी यात्रियों के लिए पर्याप्त लेगरूम प्रदान करती है।

पावरट्रेन डिटेल

इस नए मॉडल में अधिकतम 240 kW का आउटपुट है और यह 100 kWh की हाई-वोल्टेज बैटरी से लैस है। यह पहले लॉन्च किए गए Audi Q6 e-tron quattro में शामिल हो गया है, जिसका सिस्टम आउटपुट 285 kW है और दूसरी SQ6 ई-ट्रॉन है, जिसका सिस्टम आउटपुट 380 kW है।

बैटरी और रेंज

WLTP के अनुसार, ऑडी Q6 ई-ट्रॉन 641 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज प्रदान कर सकती है। कंपनी का दावा है कि ऑडी ई-ट्रॉन GT अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग का दावा करती है, जो संगत हाई-पावर चार्जिंग स्टेशनों के साथ 10 मिनट में 260 किलोमीटर की रेंज जोड़ता है।

इस नए वेरिएंट में एक रियर-व्हील ड्राइव सेटअप है, जो एक कॉम्पैक्ट लेकिन शक्तिशाली स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर द्वारा संचालित है। ऑडी के अनुसार, यह मोटर 240 kW की शक्ति प्रदान करती है और कार को मात्र 6.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पर पहुंचा देती है।

इंटीरियर और फीचर्स

Q6 ई-ट्रॉन के केबिन में 14.5 इंच का सेंट्रल कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका अपना AI अवतार है, जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे 11.9 इंच के ड्राइवर डिस्प्ले में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त, आगे की पैसेंजर सीट पर 10.9 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट है। Q6 ई-ट्रॉन में कनेक्टेड तकनीक भी है और यह ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट को सपोर्ट करती है।

Yezdi की 2.15 लाख वाली बाइक पर Free में मिल रही हजारों रुपये की

नई दिल्ली। ऑफ रोडिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए Yezdi की ओर से Adventure बाइक को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस बाइक पर हजारों रुपये की एक्सेसरीज को Free में दिया जा रहा है। बाइक को किन खूबियों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Yezdi Adventure पर मिल रही Free एक्सेसरीज

Yezdi की ओर से Adventure बाइक पर Free में कुछ खास एक्सेसरीज को दिया जा रहा है। कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी Mountain Pack में आने वाली एक्सेसरीज को पूरी तरह से फ्री में दे रही है। इस पैक की कीमत 17500 रुपये है और इसमें कंपनी की ओर से छह एक्सेसरीज को दिया जाता है। Moutain Pack में Main Cage, Knuckle Gaurds, Bar End Weights, Headlamp Grill, Crash Gaurd और पांच लीटर की दो जैरी कैन को दिया जा रहा है।

कितना दमदार इंजन

बाइक में कंपनी की ओर से 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया जाता है। जिससे 30.3 पीएस की पावर और 29.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बाइक में 220 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया जाता है, जिससे किसी भी तरह की सड़क पर इसे आसानी से चलाया जा सकता है।

कैसे हैं फीचर्स

Yezdi Adventure बाइक में कंपनी की ओर से कुछ बेहतरीन फीचर्स को दिया जाता है, जिससे ऑफ रोडिंग के समय काफी आसानी हो जाती है। इस बाइक में टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डबल डिस्क ब्रेक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स को दिया जाता है।

कितने हैं वेरिएंट

कंपनी की ओर से इस बाइक को दो वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। ग्राहकों को इस बाइक के ग्लॉस और मैट फिनिश के विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें मैट की एक्स शोरूम कीमत 2.15 लाख रुपये और ग्लॉस की एक्स शोरूम कीमत 2.20 लाख रुपये है। ग्राहक बाइक को कंपनी की वेबसाइट पर पांच हजार रुपये में ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं।

महिंद्रा ने केवल 3 दिनों में डिलीवर की XUV 3XO की 2500 से ज्यादा यूनिट, केवल इन वेरिएंट की हो रही है डिलीवरी

परिवहन विशेष न्यूज

Mahindra XUV 3XO ने बहुत से कार खरीदारों को आकर्षित किया है। कंपनी ने 3 दिनों के अंदर XUV 3XO की 2500 से अधिक यूनिट डिलीवर कर दी हैं। Mahindra XUV 3XO के केवल मिड-स्पेक वेरिएंट की डिलीवरी शुरू की है। यह एसयूवी कुल 9 वेरिएंट में उपलब्ध है। Mahindra XUV 3XO को पावरट्रेन के तीन विकल्पों के साथ पेश कर रही है।

नई दिल्ली। Mahindra ने हाल ही में XUV 3XO को लॉन्च किया है और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है। कार निर्माता ने 15 मई को एसयूवी के लिए बुकिंग शुरू की थी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत 7.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और ये सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सन जैसी कारों को टक्कर देती है।

Mahindra XUV 3XO को मिले 2500 ग्राहक

Mahindra XUV 3XO ने बहुत से कार खरीदारों को आकर्षित किया है। कंपनी ने 3 दिनों के अंदर XUV 3XO की 2500 से अधिक यूनिट डिलीवर कर दी हैं। डिलीवरी के पहले दिन ही 1500 से अधिक ग्राहक नई XUV 3XO अपने घर लाए हैं। महिंद्रा के अनुसार, पहले घंटे के अंदर 50 हजार से अधिक ग्राहकों ने एसयूवी को बुक किया था। इस एसयूवी ने महिंद्रा की पुरानी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV300 की जगह ली है।

केवल मिड-स्पेक वेरिएंट की हो रही डिलीवरी

Mahindra XUV 3XO के केवल मिड-स्पेक वेरिएंट की डिलीवरी शुरू की है। यह एसयूवी कुल 9 वेरिएंट में उपलब्ध है। जिन ग्राहकों को इसकी यूनिट मिल चुकी है, उनमें AX5, AX5 L, MX3 और MX3 Pro जैसे वेरिएंट शामिल हैं।

महिंद्रा अगले महीने से एंट्री-लेवल M1, MX2 और MX2 Pro के साथ-साथ AX7 और AX7 L जैसे टॉप-एंड वेरिएंट की डिलीवरी शुरू करेगी। डिलीवर किए जा रहे वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये से लेकर 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

इंजन और स्पेसिफिकेशन

Mahindra XUV 3XO को पावरट्रेन के तीन विकल्पों के साथ पेश कर रही है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ-साथ 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड यूनिट भी है। पावर आउटपुट 110 बीएचपी और 129 बीएचपी के बीच है, जबकि टॉर्क आउटपुट 200 एनएम और 230 एनएम के बीच है।

कार निर्माता इस एसयूवी को 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ भी पेश करता है, जिसने पेट्रोल वेरिएंट जितना आकर्षण नहीं बटोरा है। महिंद्रा के मुताबिक, बुक की गई हर पांच में से तीन XUV 3XO एसयूवी पेट्रोल वेरिएंट हैं।

पुरानी जेनरेशन के मुकाबले मारुति स्विफ्ट 2024 से क्यों मिलता है ज्यादा माइलेज

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता Maruti Suzuki ने मई 2024 में Swift 2024 को लॉन्च किया है। कंपनी ने इस कार में नया इंजन दिया है। जिसके साथ इसकी माइलेज भी काफी बेहतर हो गई है। अपनी पुरानी जेनरेशन के मुकाबले नई Swift कैसे ज्यादा Mileage ऑफर करती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुई Maruti Swift 2024

मारुति की ओर से 9 May 2024 को भारतीय बाजार में चौथी पीढ़ी की Swift 2024 को लॉन्च किया। कंपनी ने इस कार में के-सीरीज इंजन की जगह नया जेड-सीरीज इंजन दिया है। इसके साथ ही कंपनी का दावा है कि यह सबसे ज्यादा Mileage देने वाली कार है। कंपनी के मुताबिक इस कार को एक लीटर पेट्रोल में 25.75 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

क्यों मिल रहा है बेहतर Mileage

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है कि मारुति की नई स्विफ्ट 2024 का वजन पुरानी जेनरेशन के मुकाबले कम रखने से कार का माइलेज बढ़ाने में मदद मिली है।

कम मतदान क्यों होता है?

डा. वरिंद्र भाटिया

कुछ लोग स्विंग वोटर होते हैं, वे नार्मल परिस्थितियों में वोट देने की जहमत नहीं उठाते। ये लोग जब वर्तमान सरकार को हटाना होता है, तब दूसरे पक्ष के फेवर में वोट करते हैं। बाकी जो जिस पार्टी के वोटर हैं, वे तो अपनी-अपनी लॉयल पार्टी को वोट करते ही हैं। ये स्विंग वोटर ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाते हैं।

कुछ लोग स्विंग वोटर होते हैं, वे नार्मल परिस्थितियों में वोट देने की जहमत नहीं उठाते। ये लोग जब वर्तमान सरकार को हटाना होता है, तब दूसरे पक्ष के फेवर में वोट करते हैं। बाकी जो जिस पार्टी के वोटर हैं, वे तो अपनी-अपनी लॉयल पार्टी को वोट करते ही हैं। ये स्विंग वोटर ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाते हैं। परंतु अगर शत-प्रतिशत मतदान नहीं हो रहा है, तो डेमोक्रेसी के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमें मतदान को मूलभूत आवश्यकता के रूप में समझकर मतदान करना चाहिए, साथ ही औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। मतदान एक मौलिक अधिकार और एक नागरिक कर्तव्य है। इसे अनिवार्य बनाने से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे'

इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान का कम प्रतिशत लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही कम मतदान प्रतिशत से असमंजस बढ़ रहा है। लोगों का अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में इस प्रकार से कम दिलचस्पी लेना यकीनन मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए, इस मुद्दे का विश्लेषण करें। भारत में गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग को वोट एक अस्त्र जैसा लगता है जिसके इस्तेमाल से वे अपनी अहमियत जता सकते हैं। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि वोट अवश्य दें। शहरों के गरीबों में एक बड़ी संख्या प्रवासी लोगों की होती है जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं होते हैं, जबकि गांवों में कई बार मतदान केंद्र बहुत दूर होते हैं जिसकी वजह से भी कई लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। फिर भी कुल मतदान प्रतिशत में इस वर्ग के लोगों का प्रतिशत 30 से कम नहीं होता है। इनके द्वारा अल्पसंख्यकों की समर्थक पार्टी या जाति आधारित पार्टी या पैसा बांटने वाली पार्टी को वोट देने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी 20 प्रतिशत मतदान निम्न मध्यम वर्ग और कुछ मध्यम वर्ग द्वारा किया जाता है। उच्च वर्ग अक्सर मतदान से विरक्त रहता है। इस प्रकार सामान्य समय में जब हम 50 प्रतिशत मतदान देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि लोग सरकार से न तो ज्यादा खुश होते हैं, न ज्यादा असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जब सरकार निरंकुश, भ्रष्ट, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करती या निष्क्रिय प्रतीत होती है, तो मध्यम वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार बदलने के लिए बाहर निकलता है और मतदान प्रतिशत में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाती है। इस प्रकार यह देखा गया है कि जब भी मतदान 60 प्रतिशत से काफी ऊपर हो जाता है तो विपक्ष की पार्टी जीत जाती है।

जीवंत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मतदाता पूरी सक्रियता और तन्मयता से चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बने, लेकिन इस बार के चुनाव में पहले चरण से ही देखने में आया कि मतदान के रोज अनेक मतदाता अपने परिवार के साथ घूमने-फिरने निकल पड़े। कुछ कहते सुने गए कि उनके परिवार के मत न भी पड़े तो क्या फर्क पड़ेगा? जीतने वाली पार्टी तो जीत ही जाएगी। बाहरी उम्मीदवार की मौजूदगी भी कम मतदान के उभरते हुए कारणों में एक है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी होने के कारण भी मतदाता वोट करने घर से नहीं निकल रहे। चुनाव आयोग ने पहले चरण के कम वोट प्रतिशत रहने पर अपनी कोशिशें और तेज कर दी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट करने घरों से निकलें, लेकिन मतदाता की उदासीनता टूटी नहीं। दिल्ली जैसे राजधानी शहर, जहां के निवासी बनिस्बत पढ़े-लिखे और जागरूक माने जाते हैं, में भी मत प्रतिशत पिछली दफा से भी कम रह जाना वाकई चिंता की बात है। दरअसल, एक तो चुनाव में कोई लहर नहीं बन सकी है, और चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर आ सिमटा है, मगर कम मतदान को किसी भी तर्क से वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। कम मतदान चिंता की बात है। भारत के घटते मतदाता टर्नआउट के लिए पांच स्पष्ट कारण हैं। सामान्य तौर पर, पहला, बहुत से समृद्ध और शहरी निवासियों का मानना है कि सरकार पर निर्भर न होने के कारण उनके जीवन पर मतदान का बहुत कम बोझ है। दूसरा, प्रवासन के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने शहरों से बाहर निकल गए हैं। तीसरा, युवा और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को अक्सर ऐसे राजनीतिज्ञों से संबंधित करना मुश्किल हो जाता है जो आपराधिक, सामंती प्रभु या नीतिगत विशेषज्ञता के अभाव वाले सेलिब्रिटी हैं।

चौथा, कुछ लोग मतदान नहीं करते बल्कि वास्तविकता में वे मुद्दों या उम्मीदवारों से अनभिज्ञ हैं। पांचवां, मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए सेलिब्रिटी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में पूरी सफलता नहीं मिली है। आज तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवार और खुद चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहा है कि आखिर लोग वोट देने घरों से क्यों नहीं निकले? कम वोटिंग के पीछे गर्मी बड़ा कारण भले ही न हो, लेकिन एक कारण जरूर हो सकता है। कई वर्षों के बाद अप्रैल महीने में इतनी तेज गर्मी पड़ी है। इससे कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कम से कम मैं तो गर्मी की वजह से वोटिंग कम होने को बड़ा कारण नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो फिर सुबह और शाम वोटिंग प्रतिशत अधिक होता, जो अभी तक ट्रेंड में दिखाई नहीं दिया। वोटर लिस्ट में वोटर और वोट देने वालों में अंतर के कई कारण हो सकते हैं। जैसे, वोटर उस समय उस स्थान पर से कहीं कार्य के लिए बाहर चला गया। वह कार्य निजी, व्यावसायिक या नौकरी का हो सकता है। करोड़ों सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाते हैं। हालांकि उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है, लेकिन उसमें फार्मलिटी अधिक है। इसलिए बहुत से फॉर्म नहीं भरते। कई लोग नौकरी दूसरे शहरों में करते हैं, लेकिन वोट अपनी पुश्तैनी जगह ही बनवाया हुआ होता है। वोट के लिए ही अपने शहर या ग्राम खुद के खर्च से जाकर वोट के लिए ही लोग जा नहीं पाते। कुछ लोगों ने दो जगह भी वोट बनाया होता है, एक पुश्तैनी जगह, दूसरा नौकरी का शहर। वह एक ही जगह तो वोट डाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे होते हैं और होस्टल में या किराए पर रहते हैं। वे भी वोट डालने नहीं आ पाते।

वृद्ध लोग या अकेली गृहिणी भी वोट देने में संकोच करती है। कुछ लोग बीमार हो सकते हैं। कुछ लोगों की शादी होने पर दूसरी जगह जाने से या वोटर का निधन होने से भी वोट नहीं पड़ पाता। कुछ लोग स्विंग वोटर होते हैं, वे नार्मल परिस्थितियों में वोट देने की जहमत नहीं उठाते। ये लोग जब वर्तमान सरकार को हटाना होता है, तब दूसरे पक्ष के फेवर में वोट करते हैं। बाकी जो जिस पार्टी के वोटर हैं, वे तो अपनी-अपनी लॉयल पार्टी को वोट करते ही हैं। ये स्विंग वोटर ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाते हैं। परंतु अगर शत-प्रतिशत मतदान नहीं हो रहा है, तो डेमोक्रेसी के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमें मतदान को मूलभूत आवश्यकता के रूप में समझकर मतदान करना चाहिए, साथ ही औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। मतदान एक मौलिक अधिकार और एक नागरिक कर्तव्य है। इसे अनिवार्य बनाने से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि सरकार लोगों की इच्छा की प्रतिनिधि है। मतदान डेमोक्रेसी की आत्मा है। गलत मतदान/मतदान नहीं करना, तटस्थ मतदान, लालच, सम्प्रदाय, जाति, पंथ, भाषा या क्षेत्रवाद से प्रेरित होकर मतदान करना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है।

संपादकीय

हिमाचल के सियासी गुनाह-4

हम किसी एक पार्टी में गुनाह के कीड़े नहीं निकाल रहे, बल्कि इस हकीकत को बताना चाहते हैं कि राजनीति के धंधे ने प्रदेश की अमानत को गुनहगार बना दिया है। एक तरह की बंदरबांट में पैदा हो रही राजनीति का धर्म सत्ता और सत्ता का धर्म चंद नेताओं की बिसात पर मोहरे चुनना या सामने जनता के हक हकूक की निगरानी को परास्त करना। हर सत्ता ने अपने पक्ष में हामी भरने के लिए सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में नित नए हथकंडे चुन लिए, जबकि टैक्स भरता व रोजगार बांटता निजी क्षेत्र सदा दीवार के साथ खड़ा किया जाता रहा है। बातें निजी निवेश और दौरे देश-विदेश के, लेकिन हिमाचल के अपने स्थानीय निवेशक को विभागीय कार्रवाइयों के दंश या व्यापारिक प्रक्रियाओं की कठोरता में मुरझाने को छोडने का गुनाह सूली बनकर उभरता है। यही नहीं, राज्य की राजनीति ने अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए नौकरशाही या अफसरशाही का दामन थाम लिया है या इस गठजोड़ ने ईमानदार, सक्षम व कर्मठ अधिकारियों को डिब्बाबंद कर दिया। राजनीति का वीआईपी चेहरा दिखा रही पुलिस के कदमताल में कानून व्यवस्था का विराम स्पष्ट है। अब तो प्रदेश संगठित अपराध की शाखा में कसोल का नाम आते ही नशेड़ी दिखाई देता है। नूरपुर की छन्नी का जिक्र होते ही नकली शराब का अड्डा नजर आता है। अब तो हम अपनी खड्डों या नदी-नालों को देखते ही स्वीकार कर लेते हैं कि अबकी बार खनन माफिया की कमाई में कौन नेता पहलवान हो जाएगा। क्या हमने बीबीएन में माफियागिरी फैलाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया।

क्या पियाऊ बने शराब के ठेके या हर तरह के ठेकों में सियासत ने कोई गुनाह नहीं किया। आश्चर्य यह कि जब प्रदेश में कोई क्रांतिकारी पहल या बड़े फैसले की आहट होती है, तो पक्ष-विपक्ष के बीच हम अपने ही प्रदेश से गुनाह करते हैं ताकि दबाव और दबदबा बना रहे। मनाली स्की विलेज जैसी परियोजना को रोकने के लिए देव संस्कृति का इस्तेमाल सदी का सबसे बड़ा गुनाह क्यों न माना जाए। जिन्होंने कांगड़ा-ऊना के एसईजेड रोके थे या जिन्होंने आज तक धर्मशाला में हाई कोर्ट की खंडपीठ के संघर्ष को खुर्द-बुर्द किया, वे सभी कठघरों में रहेंगे। हिमाचल की समूची सियासत में एक ही तरह के आयाम ढूंढे जा रहे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं और न ही सरकारों को बदल-बदल कर नागरिक अपने अधिकारों में आसमान देख पाएंगे, बल्कि अब ऐसा समय आया है जब एक तीसरा मोर्चा पैदा हो ताकि सत्ता के संतुलन में क्षेत्रवाद, यारों की दरकार, बजट का हिसाब और पूरे हिमाचल का ख्याल रखा जाए। इसके लिए धांसू लीडरशिप चाहिए। विडंबना यह है कि प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियां आलाकमान की गुलामी में जमीनी तत्व व सियासी जरूरतों को भूल रही हैं। ऐसे में मास लीडर के बजाय आलाकमान के प्यादे खोजे जा रहे हैं। बेशक राजनीतिक प्रमुख से हमारे नेता हर सार्वजनिक मंच के अभिनेता हैं, लेकिन इनकी काबिलीयत में इनकी उपस्थिति का गुनाह युवाओं को अंधेरी गली की ओर प्रेरित कर रहा है।

हमारे सामाजिक बंटवारे, गांव की गलियां अब पंचायती राज के बंटवारे में बंट गईं। हम खुश हैं और सामने किसी सरकारी संस्थान का नामकरण नेता के नाम पर हो रहा है, लेकिन अमर शहीद के नाम पर कोई रास्ता झाडियों से अटा पड़ा रहता है। हमारे सन्नाटों में समाज के प्रतिष्ठित गैर राजनीतिक, प्रबुद्ध व सेवानिवृत्त आला अधिकारी अपनी निष्पक्षता के कारण गुमनाम किए जा रहे हैं। सभी राज्यों ने समाज के चरित्र को खानपान, भाषा, संस्कृति, ज्ञान, पहरावा व परंपराओं से एक बनाया, हम तो एक हिमाचली भाषा तक नहीं बना पाए, उस पर शांता कुमार की सरकार ने हिंदी भाषी राज्य बनाकर इस प्रदेश की पहाड़ी पहचान के साथ गुनाह किया है। हम युवाओं को सरकारी नौकरी की परेड में नंगा करके गुनाह का चाबुक चला रहे हैं।

राय

भयावह है यह गर्मी-लू

तमतमाती गर्मी और भीषण लू की चपेट में आधा भारत है, लिहाजा मौसम भयावह हो गया है। करीब 50 शहरों में तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा में भी तापमान करीब 47 डिग्री सेल्सियस रहा है। राजस्थान के फलौदी में लगातार तीसरे दिन तापमान 49 डिग्री को पार कर गया। यह देश का सबसे ज्यादा गरम इलाका रहा। ये सामान्य तापमान नहीं हैं, क्योंकि एक हद के बाद गर्मी और लू के ये थपेड़े जानलेवा साबित हो सकते हैं। देश में एक तरफ चिलचिलाती गर्मी है, तो दूसरी ओर पश्चिमी तट पर 'रेलम तूफान' ने थपेड़े मारते हुए बहुत कुछ बर्बाद किया है। कई जानें भी गई हैं। तेज हवाएं चल रही हैं और खूब बारिश का आलम है। यह विरोधाभास एक ही देश के भीतर दिख रहा है। यही जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव है। दिल्ली ही नहीं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई जैसे महानगरों में 'ताप प्रभाव और सूचकांक' स्पष्ट दिख रहा है। यह विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रपट का सारांश है। यहां पर कंकरीट या पक्का निर्माण बढने के साथ ही हरित क्षेत्र पहले की तुलना में कम हुए हैं। इसके कारण रात के समय भी तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं आ रही है। गर्मी का ऐसा प्रचंड प्रभाव है कि सडक़ों पर दौड़ रहे वाहनों के टायर पिघल रहे हैं। नतीजतन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस उबलती गर्मी के मानवीय दुष्प्रभाव भी हैं।

प्रख्यात पत्रिका 'लैंसेट' ने अध्ययन किया है कि यह मौसम मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप और किडनी के मरीजों के लिए बेहद गंभीर दुष्प्रभावों वाला है। चिकित्सकों का मानना है कि लोगों को काम से बाहर जाना उनकी विवशता है, लिहाजा प्रचंड गर्मी से लोग 'डिहाइड्रेशन' का शिकार हो रहे हैं। उससे किडनी की कार्यक्षमता सीधे ही प्रभावित होती है। उससे कई और बीमारियां बढ़ सकती हैं। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के सभी 26 अस्पतालों में 2-3 बिस्तर आरक्षित किए जा रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 5 बिस्तर आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र का आकलन है कि तमतमाती गर्मी जून में भी भयावह होगी, क्योंकि इस बार गरम लू के दिन दोगुना होंगे। सबसे ज्यादा असर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उप्र, गुजरात और मध्यप्रदेश आदि राज्यों में दिखेगा। उत्तर-पश्चिम राज्यों में जून में सामान्य रूप से गरम लू के 3 दिन होते हैं, लेकिन इस बार कमोबेश 6 दिन रहने की आशंका है।

रात का तापमान भी 4-6 डिग्री अधिक रहेगा। गर्मी के साथ-साथ उमस भी बढ़ेगी। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रपट के मुताबिक, शहरों में नमी ज्यादा होने और तापमान में बढ़ोतरी के चलते वहां का मौसम पहले से ज्यादा असहनीय होता जा रहा है। इस पर तुरंत प्रबंधन अनिवार्य है। हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी, जलाशयों के निर्माण के साथ-साथ भवनों की संरचना में ऐसे बदलाव लाए जाने चाहिए, जिससे वे तापमान के ज्यादा अनुकूल हो सकें। ऐसे गरम मौसम में चिकित्सकों की सलाह है कि इस मौसम में कई वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में कुछ खाने के बाद उल्टी आने लगती है या फिर पेट में जलन होने लगती है। यह पाचन-तंत्र की गड़बड़ी का पहला संकेत है, लिहाजा गर्मियों में तरबूज और खरबूजे का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। इन फलों में पानी होता है। ये शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। ऐसे मौसम में नारियल का पानी, खीरा, दही, पुदीना, आम, लीची, आड़ू, संतरा, मौसमी, खुबानी, अनानास, अनार आदि भी फायदेमंद होते हैं।

मतदान में युवाओं की अत्यावश्यक भूमिका

युवा वोट को प्रोत्साहित करने का सबसे स्पष्ट तरीका शिक्षा और जागरूकता फैलाना है। लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है और युवाओं को यह बात समझनी चाहिए

देश में सबसे बड़ा महापर्व चुनावी पर्व देश में पहले चरण के साथ शुरू हो गया है जिसको लेकर सभी के मन में व विश्व की नजर में अनेक कयास लगाए जाएंगे क्योंकि भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र की इस सफलता का आधार देश का जागरूक मतदाता माना जाता है। यह महापर्व कई माध्यमों से होकर गुजरेगा जिसमें चुनाव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करता है। चुनाव लोकतंत्र के उस विचार को सामने रखता है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है कि शक्ति 'हम लोग' के पास है। 'लोगों' ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य दिया जो न केवल उनके अधिकारों और व्यक्ति की रक्षा करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि न्याय और निष्पक्षता के ऐसे सिद्धांत हमेशा व्यवहार में हों और यह भारत के संविधान के रूप में जाने वाले चार्टर द्वारा सुनिश्चित किया गया हो। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन व्यवस्था का आधार व प्राण होते हैं। प्रत्येक चुनावों में निश्चित उम्र पूरी कर चुके अनेकों नव मतदाता इस चुनावी पर्व की बेला में सरीक होते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव सात चरणों और 44 दिनों में होंगे, वोटों की गिनती 4 जून को होगी। यह घोषणा देश के सबसे बड़े पर्व की एक औपचारिक शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इतना विशाल सफल मतदान व निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आजादी के बाद से देश में मतदाताओं की संख्या छह गुना बढ़ चुकी है।

देश में कुल मतदाताओं की संख्या बढक़र 96 करोड़ हो गई है। साल 1951 में देश में कुल मतदाता 17.32 करोड़ थे, जो अब बढक़र 96 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग के लिए चिंता की बात यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में करीब एक-तिहाई, यानी लगभग 30 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया था। ऐसे में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए चुनाव आयोग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कहीं फिल्म जगत के, तो कहीं खेल जगत के धुरंधरों को ब्रांड एंबेसेडर बनाकर नए मतदाताओं को मतदान करने हेतु चुनाव आयोग प्रेरित कर रहा है। विभिन्न माध्यमों से हर प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग जिला से लेकर मंडल स्तर तक स्वीप कार्यक्रम को गति से दौड़ा रहा है तथा नए पंजीकरण किए जा रहे हैं। लेकिन चुनावों में मतदान प्रतिशतता पर सदैव नजरें बनी रहती हैं। चुनावों में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए मतदान प्रतिशतता बढ़ाने की कड़ी में महती भूमिका है। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जहां इतने अधिक चरणों में मतदान व मतदाताओं की विशाल

संख्या चुनाव को देश का सबसे बड़ा पर्व बना देती है। इस पर्व का आयोजन सही मायने में तभी होगा जब अधिक से अधिक मतदाता अपने लोकतान्त्रिक अधिकार का प्रयोग कर सरकार का चुनाव करके इस पर्व की महाबेला में अपनी आहुति मत के रूप में दें। इन दिनों एक बात और महत्वपूर्ण है। आप किसी भी पार्टी का पक्ष लेने से पहले उसका घोषणा पत्र जरूर पढ़ें। लोकतंत्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है।

खासकर स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थी स्वयं जागरूक बनकर अनिवार्य रूप से मतदान करें और अपने आसपास दूसरों को भी प्रेरित कर जागरूक मतदाता बनने में योगदान दें। लोकतंत्र में मतदान का महत्व समझना और दूसरों को समझाना एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे देश का प्रत्येक नागरिक समझ ले तो समाज को मजबूत आधार मिल सकेगा। खास तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने स्वयं आगे आना चाहिए। अनेक जागरूकता कार्यक्रम समाज में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। मतदान के दिन अवकाश कोई घूमने के लिए नहीं, बल्कि देश के महापर्व व लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए होता है। इस बात को युवाओं को समझना होगा, तभी देश में सबसे अधिक युवा मतदाता होने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जहां राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, वहीं मतदाताओं की नब्ज को टटोलने का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन चुनावों में मतदाताओं के लिए जागरूक होना जरूरी है, ताकि देश के इस उत्सव में हम सही नेताओं का चुनाव कर सकें। अगर मतदाता जागरूक नहीं होंगे तो कभी अपने नेता का सही चुनाव भी नहीं कर पाएंगे। नेताओं को भी चाहिए कि चुनावों के दृष्टिगत ही मतदाताओं को अपना भगवान न मानें, बल्कि चुने जाने के पश्चात 5 वर्षों तक उनको भगवान मानें। तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। इसलिए मतदाताओं को भी चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के लालच में न आकर अपने को और अपने कीमती वोट को न बेचें, बल्कि निर्भीक व निडर होकर अपना मतदान करें। भारत में चुनाव को अक्सर शासन के प्रति लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के साथ-साथ संवैधानिक रूप से संचालित समाज के महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में देखा जाता है। शासन की शक्ति लोगों के पास बनी रहे और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा इसे सुनिश्चित करने के साधनों में से एक है।

चुनाव कानूनों में आजादी के बाद से काफी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण में युवा ही संपत्ति हैं, इसका एहसास 1988 में किया जा सकता है, जब 61वें संशोधन विधेयक ने मतदाताओं की पात्रता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। इस बदलाव से युवाओं को अपने देश की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद थी। हालांकि, यह काफी हद तक असफल रहा, क्योंकि 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में युवाओं की भागीदारी कम रही। युवा वोट को प्रोत्साहित करने का सबसे स्पष्ट तरीका शिक्षा और जागरूकता फैलाना है। लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है और युवाओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपने वोट की कीमत जानें। युवाओं को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र का जश्न मनाने और उनकी चिंताओं को सुनने के लिए मतदान करना चाहिए। युवाओं में आम समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए।

भीड़ जुटा, मेहरबानी पा'

इधर पैसे उनके हाथ पर तो उधर बिजली का मीटर आपकी दीवार पर। सेंक्शन बाद में होता रहेगा। कम से कम बिजली वालों के ऑफिस जलील होने से तो बचे। चप्पलों का क्या, उनकी किस्मत में तो बात बात पर घिसना लिखा है। आपके घर बिजली आ गई तो आपको और आपको चाहिए भी क्या। अपने स्तर पर जो अपने घर में बिजली का मीटर लगाने चलोगे तो टकराते रहो हर बिजली विभाग के ईमानदार कर्मचारी की कुर्सी से अपना सिर। सुनते रहो उनके कभी ये बहाने तो कभी वो बहाने। अभी मीटर नहीं है। अभी बिजली की तार नहीं है। अभी मीटर लगाने वाला नहीं है। अभी.सरकारी कर्मचारी के पास जितने काम करने के तरीके नहीं होते उससे अधिक काम न करने के बहाने होते हैं। इधर पैसे उनके हाथ पर तो उधर बंद पड़े राशन कार्ड के बिना ही राशन आपके थैले में। राशन कार्ड बाद में खुलता रहेगा। पहले चैन से सरकारी राशन घर ले जाइए। अपना चूल्हा जलाइए। मुफ्त का राशन चौड़े होकर खाइए। फ्री का खाने में जो मजा है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। आज की राजनीति मुद्दों की राजनीति नहीं, भीड़ की राजनीति हो गई है। आज के नेताश्री सिद्धांतों पर बात नहीं करते, अपनी रैली में भीड़ पर बात करते हैं। आज के नेता अपनी रैली में भीड़ देखकर प्रसन्न होते हैं।

किसी भी नेता का कद आज उसकी रैली में आई भीड़ नहीं, लाई भीड़ तय करती है। कल उनकी पार्टी के यही जनाब मेरे घर आए। तन से लेकर मन तक परेशान से दिखे। मैंने पूछा, 'भैया जी! परेशान काहे हो? जन सेवा तो टनाटन चल रही है न?' 'संडे को अपने नेता की रैली हो रही है', उनके कुरते पर चिंता की सलवटें। 'तो?' 'तो क्या! नेताजी ने अपने तमाम वर्करों को आदेश दिया है कि उनकी रैली में जो जितनी भीड़ लाएगा, वह पार्टी में उतनी ही मेहरबानी पाएगा।' 'मेहरबानी बोले तो?' 'मेहरबानी बोले तो ये कि नेता जी की रैली को सफल बनाने के लिए भीड़ लाओ और भविष्य में कमाने के मनवांछित अधिकार पाओ।' 'मतलब?' 'जो मैं अबके नेताजी की रैली में सबसे अधिक भीड़ ले गया तो समझो पार्टी में मेरा कद और बढ़ गया। आज की राजनीति में जनता की सेवा करके कार्यकर्ता का कद नहीं बढ़ता, अपने नेताओं की रैली में भीड़ जुटाने से बढ़ता है। कद बढना बोले तो जनता की सेवा करने की प्रमोशन! मैं बी क्लास वर्कर से ए क्लास वर्कर हो जाऊंगा। मसलन अभी तक मैं बिजली पानी के मीटर दिलवाने के ही अधिकार रखता हूं। गली मोहल्ले में गंदी नालियों के गंद के नाम पर खाने का अधिकार रखता हूं।

पर अबके जो उनकी रैली में हजार से अधिक भीड़ जुटा गया तो समझो कल को अपने शहर में किसी की भी ट्रांसफर करवाने-रुकवाने का अधिकार भी मेरे पास आ जाएगा। जिस तरह अमीर से अमीर जनता फ्री के आटे की भूखी होती है, उसी तरह बड़े से बड़ा नेता अपनी रैली में भीड़ का भूखा होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अबके जैसे कैसे भी हो, हजार से अधिक भीड़ उनकी रैली में पहुंचा अपना कद ऊंचा करूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है।' कह वे मेरा मुंह ताकने लगे। 'मेरी जरूरत! तुम्हें तो पता है कि मेरे घर में मेरी बीवी तक मेरा कहा नहीं मानती। ले-देकर हम घर में तीन की ही भीड़ है। ऐसे में', मैंने अपनी मजबूरी उनके सामने रखी तो वे बोले, 'देख लो! मेरे नहीं, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। मनचाहा स्टेशन दिलवा दूंगा कल को! वर्ना फिर मत कहना कि यारज्यादा नहीं, मैं तुम्हें केवल बीस बंदे जुटाने का टारगेट दे रहा हूं। मैं नहीं जानता, कहां से जुटाने हैं, ये तुम जानो। अपनी बीवी को मनाओ! बंदे कहीं से भी लाओ! कैसे भी लाओ। पर मुझे मेरे झुंड में बीस बंदे नेता जी की रैली में तुम्हारे साथ खड़े दिखने चाहिएं। नेता जी ने कहा है कि अबके रैली में हर वर्कर द्वारा अपने साथ लाई भीड़ की हाजिरी लगेगी', और अपना टारगेट मुझे सौंप वे आगे हो लिए। सोच रहा हूं, नेता जी की रैली वाले दिन लेबर चौक पर जाकर वहां से बीस क्या, तीस लेबर वाले अपने साथ ले मैं भी अपने मनचाहे स्टेशन के साथ-साथ अपनी पेंडिंग पड़ी प्रमोशन पक्की कर लूं। वैसे भी सरकारी नौकरी में आकर नौकरी करता ही कौन है? सब अपने अपने मनचाहे स्टेशन बचाने-पाने की जुगाड़ में ही तो लगे रहते हैं, प्रमोशन के लिए इधर उधर नेताओं के आगे पीछे बजे रहते हैं।

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को दी चेतावनी, कहा- नियमों का अनुपालन करें सुनिश्चित

17 मई को एक सम्मेलन को संबोधित करते रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) को चेतावनी दी है कि वे विनियामक द्वारा मुद्दों को बताए बिना अनुपालन सुनिश्चित करें। इस सम्मेलन में देश में एआरसी के टॉप मैनेजमेंट ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सही काम करने में विफल रहने के लिए यह बहाना है जिसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।...

मुंबई। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने बढ़ते विनियामक उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) को चेतावनी दी है कि वे विनियामक द्वारा मुद्दों को बताए बिना अनुपालन सुनिश्चित करें।

17 मई को एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से विनियमन प्लस दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करूंगा, जहां आप न केवल विनियमन के अक्षरशः अनुपालन करें, बल्कि इसकी भावना का भी अनुपालन करें। बता दें कि इस सम्मेलन में देश में एआरसी के टॉप मैनेजमेंट ने भाग लिया था।

स्वामीनाथन ने कहा कि अक्सर हमें अपनी टिप्पणियों को लेकर प्रतिवेदन मिलते रहते हैं। इनमें कहा जाता है कि यह उद्योग की गतिविधियां हैं या आरबीआई से इस बारे में स्पष्टीकरण आना बाकी है। कभी-कभी परिपत्रों की गलत या अपनी समझ के साथ व्याख्याएं की जाती हैं।

उन्होंने कहा कि सही काम करने में विफल रहने के लिए यह बहाना है जिसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। एआरसी निदेशक मंडलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों का सही तरीके से पालन करें और नियामक को उन्हें इस बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़े।

कब होगा एआरसी की क्षमता का बेहतर उपयोग

स्वामीनाथन ने कहा कि व्यवस्था के भीतर दबाव वाली संपत्तियों के समाधान के लिए एआरसी की क्षमता का केवल तभी बेहतर उपयोग हो सकता है, जब संचालन व्यवस्था मजबूत हो और गतिविधियों के स्तर पर नीतियों का पालन हो।

उन्होंने कहा कि कुछ एआरसी, कानून और नियमों के तहत उन्हें दिए गए अधिकार का पूरा लाभ उठाते हुए नियमों को अनदेखी कर लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए नये तरीकों का उपयोग करते पाये गये हैं।

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि कार्यस्थल पर जांच के दौरान हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां एआरसी का इस्तेमाल किया गया है या उन्होंने खुद को इस्तेमाल करने की अनुमति दी।

यह भी पढ़ें- RBI: कैसे काम करता है प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी का ऐसे करें इस्तेमाल

जोखिम प्रबंधन जैसे कार्यों को देना होगा महत्व

उन्होंने कहा कि कई मामलों में 'सिक्योरिटी रिसीट' (एसआर) जारी करने और निश्चित अवधि पर होने वाले मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी है।

स्वामीनाथन ने कहा कि निदेशक मंडलों को जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक ऑडिट जैसे कार्यों को उचित महत्व देना चाहिए। ये कार्य जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ संगठन की प्रतिष्ठा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पेटम-अडानी डील की अफवाह के बाद चढ़ गए पेटीएम शेयर, अब इतनी है 1 स्टॉक की कीमत

पेटम-अडानी आज पेटीएम के शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। शेयर में आई तेजी की वजह मीडिया रिपोर्ट्स है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया था कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) फिनटेक फर्म यानी पेटीएम में हिस्सेदारी हासिल करेंगे। इन दोनों कंपनियों ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में गिरावट होने के बाबजूद आज पेटीएम के शेयर (Paytm Share) तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 29 मई 2024 को पेटीएम के शेयर 5 फीसदी उछलकर अपर सर्किट को टच किया है। आपको बता दें कि पेटीएम (Paytm) ब्रांड की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications Ltd.) है। बीएसई पर स्टॉक 4.99 प्रतिशत चढ़कर 359.55 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर, यह 4.99 प्रतिशत बढ़कर 359.45 रुपये पर पहुंच गया।

पेटीएम के शेयर में क्यों आई तेजी

कई मीडिया रिपोर्टेस में दावा किया जा रहा था कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) फिनटेक फर्म यानी पेटीएम में हिस्सेदारी हासिल करेंगे। पेटीएम और अदाणी ग्रुप ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी पेटीएम का संचालन करने वाली वन97 कम्युनिकेशंस में हिस्सेदारी खरीदना चाह रहे हैं। कहा जा रहा था कि गौतम अदाणी हिस्सेदारी के लिए पेटीएम के अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा के साथ बातचीत कर रहे हैं।

कैसे काम करता है प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी का ऐसे करें इस्तेमाल

RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में तीन नए विकल्प पेश किए है जो रेगुलेटरी प्रोसेस को बेहतर करने और रिटेल इंवेस्टमेंट को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं और प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपकी मदद के लिए यहां पूरे प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं।

नई दिल्ली। बीते मंगलवार को RBI ने गुलेटरी प्रोसेस को बढ़ाने,रिटेल इंवेस्टमेंट को आसान बनाने और फिनटेक सेक्टर में बड़े स्तर पर डेटा देने के लिए तीन नई सुविधा की शुरुआत की है। इसमें प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी को शामल किया गया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आप RBI की इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि यहां हम आपको बता रहे हैं कि इन सर्विसेज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

प्रवाह पोर्टल

- पोर्टल की बात करें तो यह सुरक्षित सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो आपको और संस्थानों को RBI से
- यह एक केंद्रीकृत, सुरक्षित वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो व्यक्तियों या संस्थाओं को RBI से रेगुलेटरी अनुमोदन, लाइसेंस और अथोरिटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है।
- इस पोर्टल पर आपको RBI से जुड़ी अलग-अलग रेगुटेलरी और सुपरविजरी डिपार्टमेंट के 60 एप्लिकेशन मिल सकते हैं।
- इसके अलावा आवेदन के बाद इससे आवेदक अपने एप्लिकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और समय पर निर्णय पा सकते हैं।
- इसकी खास बात ये है कि यूजर पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अपने आवेदन स्थिति को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते है। अपने आवेदन के बारे में RBI द्वारा उठाए गए किसी भी स्पष्टीकरण या प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। साथ ही एक निश्चित समय सीमा में रिजर्व बैंक से जवाब पा सकते हैं।

रिटेल डायरेक्ट

- रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एक रिटेल इंवेस्टमेंट ऐप है, जो निवेशकों को उनके स्मार्टफोन पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी (जी-सेक) में ट्रांजेक्शन करने का एक सहज और सुविधाजनक तरीका देता है।
- आपको बता दें कि इस ऐप से प्राइमरी और सिकेंडरी दोनों मार्केट में जी-सेक खरीदने और बेचने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

कैसे करें रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का उपयोग

- सबसे पहले Google Play Store

या Apple ऐप स्टोर के जरिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।

- इसके बाद आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता खोले और अपना पूरा नाम, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और आवासीय पता जैसी जानकारी भरें।
- अब ऐप में लॉग इन करें और सरकारी सिक्योरिटीज (जी-सेक) में ट्रांजेक्शन शुरू करने के लिए डैशबोर्ड के बगल में 'प्राइमरी मार्केट ऑप्शन चुनें।
- इसके बाद ऑक्शन वॉच से बोली लगाने के लिए कोई भी सिक्योरिटी चुनें और 'ऑक्शन' विंडो में राशि दर्ज करें।
- बोली लगाने के समय या बोली विंडो बंद होने से पहले UPI और नेट बैंकिंग जैसी सेवाओं का उपयोग करके अपनी बोलियों को फंड दें।
- इसके बाद ऑक्शन शुरू करें और आपका काम हो गया।

क्या है फिनटेक रिपॉजिटरी ?

फिनटेक रिपॉजिटरी का उद्देश्य है कि वह RBI की समझ बढ़ाने में मदद करने के लिए विनियमित और अनियमित दोनों तरह की फिनटेक फर्मों पर व्यापक डेटा देकर भारतीय फिनटेक क्षेत्र के बारे समझा सके। यह रिपॉजिटरी फिनटेक पर इनसाइट्स देता है,जो निति निर्माताओं और उद्योग प्रतिभागियों के लिए मददगार होती है।

S&P ग्लोबल ने बदली भारतीय जीडीपी ग्रोथ की रेटिंग, स्टेबल से किया पॉजिटिव

परिवहन विशेष न्यूज

रेटिंग एजेंसी SP ने इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ की रेटिंग को अपग्रेड किया है। इस बार रेटिंग फर्म ने इसे स्थिर से बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। SP के अनुसार भारत की मजबूत इकोनॉमी ग्रोथ ने क्रेडिट मेट्रिक्स पर पॉजिटिव रिस्पांस डाला है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की मजबूत इकोनॉमी ग्रोथ ने क्रेडिट मेट्रिक्स पर पॉजिटिव रिस्पांस डाला है।

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी S&P ने एक बार फिर से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ की रेटिंग को अपग्रेड किया है। इस बार रेटिंग फर्म ने इसे स्थिर से बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। S&P के अनुसार भारत की मजबूत इकोनॉमी ग्रोथ ने क्रेडिट मेट्रिक्स पर पॉजिटिव रिस्पांस डाला है।

आपको बता दें कि BBB की रेटिंग सबसे निचले स्तर की मानी जाती है।

भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ा है, लेकिन राजकोषीय घाटा को कम करने की कोशिश जारी है। हमें उम्मीद है कि भारत की बुनियादी बातें 2-3 वर्षों में विकास की गति में सहायक होंगी।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अगर राजकोषीय घाटा कम हो जाता है तो भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर सकती है। भारत सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत पर आ जाएगा, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.8 प्रतिशत था। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक घाटे को 4.5 प्रतिशत पर लाया जाए।

इन मामलों में बढ़ सकती है रेटिंग

एसएंडपी ने कहा कि अगर भारत सतर्क राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनाता है जो आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाते हुए सरकार के बढ़े हुए डेट और ब्याज के बोझ को कम करता है तो वह अगले 2 वर्षों में भारत की संप्रभु रेटिंग को अपग्रेड कर सकता है। एसएंडपी ने भारत के प्रति दृष्टिकोण को संशोधित कर स्थिर से सकारात्मक कर दिया।

एसएंडपी अमेरिका में स्थित एजेंसी है। एसएंडपी के अनुसार अगर भारत का राजकोषीय घाटा सार्थक रूप से कम हो जाता है यानी सकल घरेलू उत्पाद 7 प्रतिशत से नीचे आ जाता है तो वह रेटिंग बढ़ा सकती है।

अगर आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में निरंतर और पर्याप्त सुधार देखने को मिलते हैं तब भी एसएंडपी रेटिंग को अपग्रेड कर सकता है।

दुनिया की तीन प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों - एसएंडपी, फिच और मूडीज - ने भारत को सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग दी है। हालाँकि, फिच और मूडीज का अपनी रेटिंग पर दृष्टिकोण अभी भी स्थिर है। रेटिंग को निवेशकों द्वारा देश की साख के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है और इसका उधार लेने की लागत पर प्रभाव पड़ता है।

इंडिगो ने महिला यात्रियों को दिया तोहफा, सीट सलेक्शन के लिए शुरू किया नया फीचर

परिवहन विशेष न्यूज

Indigo ने महिला यात्रियों के लिए नया फीचर शुरू किया है। इंडिगो ने इसको लेकर प्रेस रिलीज जारी की। एयरलाइन ने बताया कि इस फीचर के जरिये महिलाएं वेब चेक-इन के समय उन सीटों के बारे में जान सकती हैं जो अन्य महिला यात्रियों द्वारा पहले ही बुक की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने महिलाओं के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के जरिये महिलाएं वेब चेक-इन के समय उन सीटों के बारे में जान सकती हैं जो अन्य महिला यात्रियों द्वारा पहले ही बुक की जा चुकी हैं। एयरलाइन ने मार्केट रिसर्च करने के बाद यह फीचर शुरू किया है।

इंडिगो ने आज प्रेस रिलीज जारी की थी। प्रेस रिलीज में एयरलाइन ने कहा कि वह महिलाओं के लिए नई सुविधा पेश कर रहे हैं। इस सुविधा का उद्देश्य महिला यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को और अधिक आरामदायक बनाना है।

इंडिगो ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि न्यू फ्रेंडली सीट सलेक्शन फीचर मार्केट रिसर्च के बाद पेश किया गया है। वर्तमान में यह #GirlPower के तहत यह फीचर शुरू किया है। इस फीचर में महिला यात्री वेब चेक-इन के दौरान अन्य महिला यात्रियों द्वारा बुक की गई सीटों के बारे में जान पाएगी। यह विशेष रूप से महिला यात्रियों - एकल के साथ-साथ पारिवारिक बुकिंग के हिस्से के लिए भी तैयार किया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंडिगो 60 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है। इस साल अप्रैल 2024 में 80 लाख यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइन से यात्रा की।

लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले लाल रंग में बाजार, वेट-एंड-वॉच मोड में हैं निवेशक

नई दिल्ली। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha election 2024) के नतीजों का एलान होगा। उम्मीद की जा रही है कि चुनावी नतीजों के बाद शेयर बाजार (Share Market) में शानदार तेजी देखने को मिलेगी।

वैसे तो चुनावी नतीजों से पहले बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला है। पिछले कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार ने नई बुलिंदियों को छुआ था। वहीं, इस हफ्ते बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अगर आज की बात करें तो शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है।

इस हफ्ते कैसा है बाजार

आज सुबह 9.31 बजे सेंसेक्स 74,906.69 अंक और निफ्टी 22,800.50 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं सोमवार और मंगलवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। पिछले दो सप्ताह के आधार पर सेंसेक्स 3,600 अंक से अधिक उछला।

बाजार में जारी उतार-चढ़ाव को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि चुनावी नतीजों से पहले निवेशकों को जोखिम से बचने के लिए उच्च स्तर पर मुनाफावसूली मदद कर सकता है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि चुनावी नतीजों से पहले बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहेगा। अगर इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में DII (Domestic Institutional Investors) द्वारा लगातार खरीदारी की जा रही है।

एचडीएफसी बैंक ने लिया बड़ा फैसला, अब इतने रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर नहीं आएगा SMS

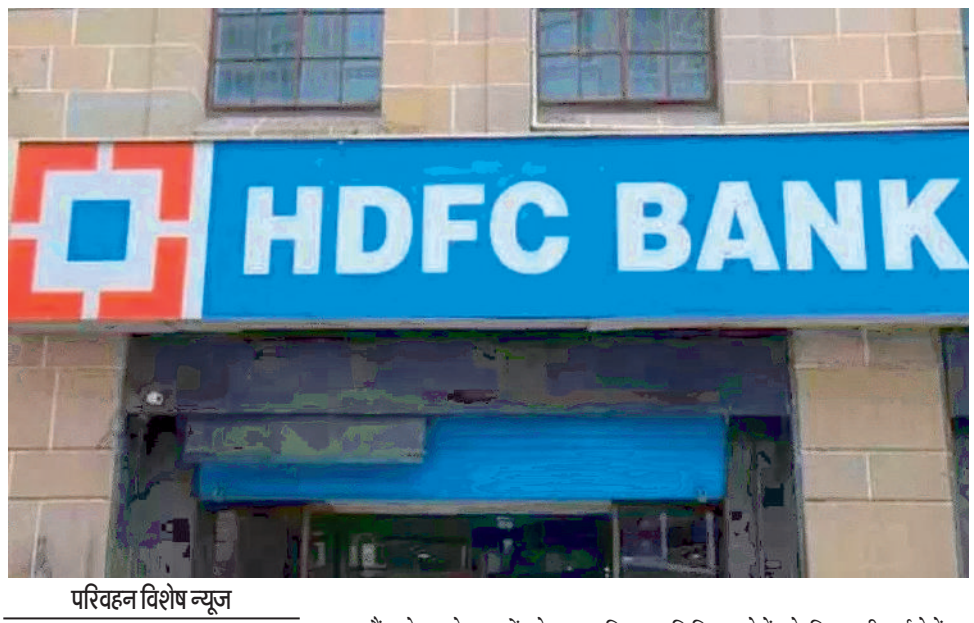

परिवहन विशेष न्यूज

HDFC Bank 25 जून 2024 के बाद से ग्राहकों को 100 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन (UPI Transaction) पर मैसेज अलर्ट नहीं भेजेगा। वहीं ग्राहकों को 500 रुपये तक के अमाउंट क्रेडिट होने पर भी मैसेज नहीं आएगा। लेकिन बैंक ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन पर ई-मेल अलर्ट भेजेगा। बैंक ने कस्टमर से कहा है कि वह जल्द से जल्द ई-मेल आईडी अपडेट करें।

नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) है। बैंक अपने ग्राहक को हर छोटे-मोटे लेनदेन होने पर मैसेज अलर्ट भेजता है। लेकिन, बैंक ने अब SMS Alert को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।

बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया कि 25 जून 2024 के बाद से ग्राहकों को 100 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन (UPI Transaction) पर मैसेज अलर्ट नहीं आएगा। वहीं 500 रुपये तक के अमाउंट क्रेडिट होने पर भी मैसेज अलर्ट नहीं भेजा जाएग।

बैंक ने ग्राहकों को बताया कि भले ही एसएमएस अलर्ट नहीं आएगा। लेकिन, ग्राहकों हर ट्रांजैक्शन पर ई-मेल अलर्ट मिलेगा। सभी ग्राहकों को सुचारू रूप से ई-मेल अलर्ट मिले इसके लिए बैंक ने ई-मेल आईडी अपडेट करने के लिए कहा है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन औसत वैल्यू में नरमी

भारत में डिजिटल माध्यमों से भुगतान नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है, क्योंकि इसके नागरिक तेजी से इंटरनेट पर लेनदेन के उभरते तरीकों को अपना रहे हैं। यहां तक कि भारत में रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम (UPI Payment System) बेहद लोकप्रिय हो गई है और इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है।

भारत में डिजिटल भुगतान में यूपीआई (UPI) की हिस्सेदारी 2023 में 80 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। वर्ष 2022 आंकड़ों के अनुसार आज दुनिया के लगभग 46 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन भारत में होता है।

हम भले ही छोटे लेनदेन के लिए यूपीआई करना पसंद करते हैं। लेकिन, पिछले कुछ सालों में यूपीआई के जरिये हो रहे लेन-देन की औसत वैल्यू में नरमी देखने को मिली है। वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में यूपीआई की औसत वैल्यू 1,648 रुपये थी जो साल 2023 की दूसरी छमाही में 1,515 हो गई है। यूपीआई के औसत वैल्यू से हम समझ सकते हैं कि देश में यूपीआई के जरिये छोटे लेन-देने ज्यादा हो रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयुक्त ने तीन आदेश जारी किये

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर : भारत निर्वाचन आयुक्त ने तीन आदेश जारी किये हैं । चुनाव आयुक्त ने विधायक प्रशांत जगदेव पर पोलिंग बूथ में कथित तौर पर ईवीएम तोड़ने के मामले की जांच तेज करने का आदेश दिया है ।इसी तरह चुनाव आयोग ने भारतीय पुलिस सेवा के कार्यरत अधिकारी डीएस कुट्टे को निलंबित कर दिया है ।चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है । आईपीएस डीएस कुट्टे मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे । चुनाव प्रक्रिया में अनैतिक हस्तक्षेप के आरोप में निलंबित किया गया। निलंबन अवधि के दौरान वह स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्य करेंगे। भारत के चुनाव आयुक्त ने कल 3 बजे तक वहां रिपोर्ट करने का आदेश दिया है।

उधर, चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशीष सिंह की मेडिकल जांच का आदेश दिया है । इस संबंध में आयोग ने भुवनेश्वर एम्स के निदेशक को एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है । आशीष को 30 मई तक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने का भी आदेश दिया गया है । आशीष सिंह चार मई से मेडिकल अवकाश पर हैं ।

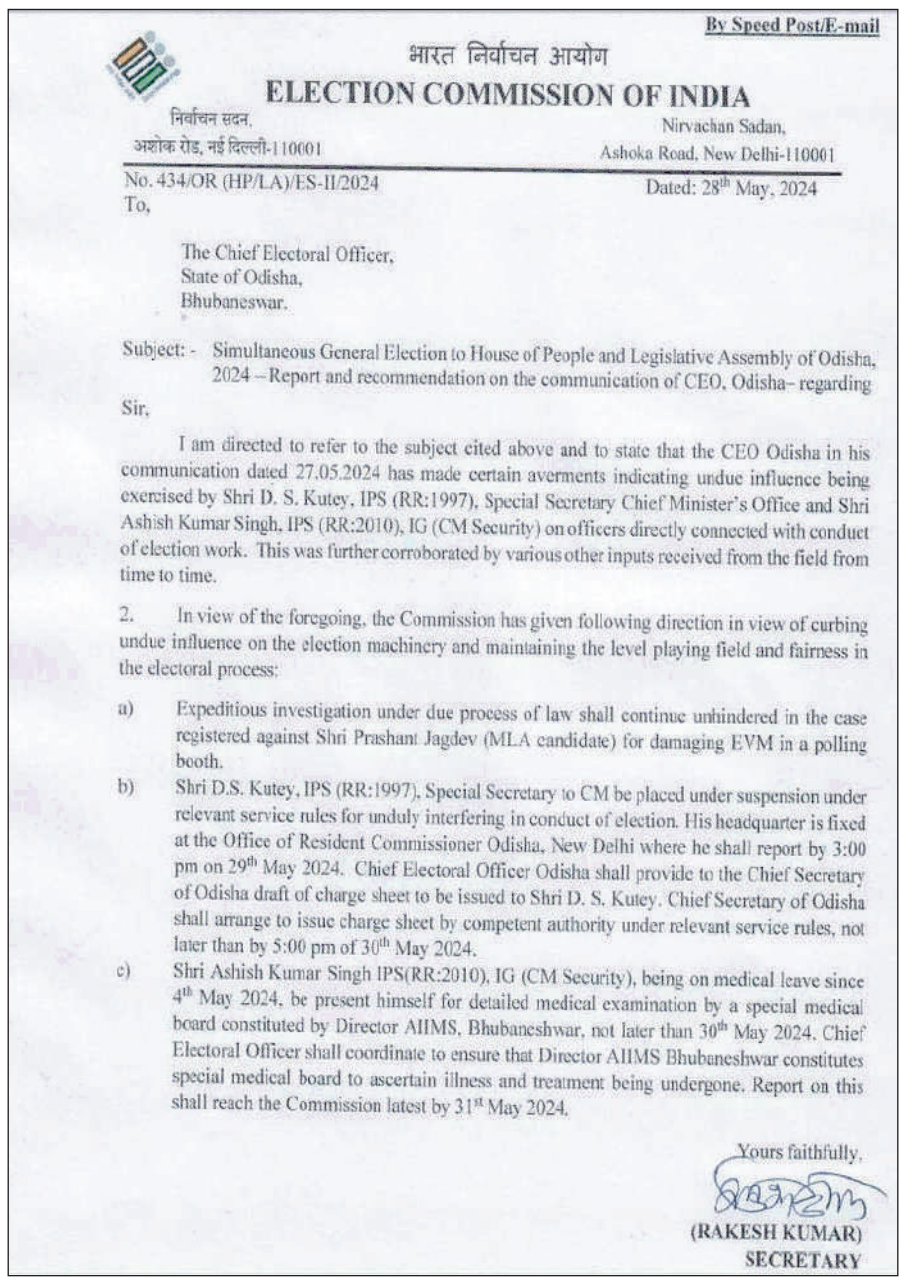

By Speed Post/E-mail

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 434/OR (HP/LA)/ES-II/2024 Dated: 28th May, 2024

To,

The Chief Electoral Officer,
State of Odisha,
Bhubaneswar.

Subject: - Simultaneous General Election to House of People and Legislative Assembly of Odisha, 2024 – Report and recommendation on the communication of CEO, Odisha- regarding

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to state that the CEO Odisha in his communication dated 27.05.2024 has made certain averments indicating undue influence being exercised by Shri D. S. Kutey, IPS (RR:1997), Special Secretary Chief Minister's Office and Shri Ashish Kumar Singh, IPS (RR:2010), IG (CM Security) on officers directly connected with conduct of election work. This was further corroborated by various other inputs received from the field from time to time.

2. In view of the foregoing, the Commission has given following direction in view of curbing undue influence on the election machinery and maintaining the level playing field and fairness in the electoral process:

a) Expeditious investigation under due process of law shall continue unhindered in the case registered against Shri Prashant Jagdev (MLA candidate) for damaging EVM in a polling booth.

b) Shri D.S. Kutey, IPS (RR:1997), Special Secretary to CM be placed under suspension under relevant service rules for unduly interfering in conduct of election. His headquarter is fixed at the Office of Resident Commissioner Odisha, New Delhi where he shall report by 3:00 pm on 29th May 2024. Chief Electoral Officer Odisha shall provide to the Chief Secretary of Odisha draft of charge sheet to be issued to Shri D. S. Kutey. Chief Secretary of Odisha shall arrange to issue charge sheet by competent authority under relevant service rules, not later than by 5:00 pm of 30th May 2024.

c) Shri Ashish Kumar Singh IPS(RR:2010), IG (CM Security), being on medical leave since 4th May 2024, be present himself for detailed medical examination by a special medical board constituted by Director AIIMS, Bhubaneshwar, not later than 30th May 2024. Chief Electoral Officer shall coordinate to ensure that Director AIIMS Bhubaneshwar constitutes special medical board to ascertain illness and treatment being undergone. Report on this shall reach the Commission latest by 31st May 2024.

Yours faithfully,

(RAKESH KUMAR)
SECRETARY

मिजोरम में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को वोट डालने की अनुमति देने की मांग, राज्यसभा सांसद ने EC को लिखा पत्र

मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के वनलालवेना ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि 1047 पुलिस कर्मियों को वोट डालने की अनुमति दी जाए क्योंकि वे अन्य राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर थे। पुलिसकर्मी 19 अप्रैल को मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव के समय अपना वोट डालने में विफल रहे क्योंकि वे चुनाव ड्यूटी पर बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गए थे।

आइजल। मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के वनलालवेना ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि 1,047 पुलिस कर्मियों को वोट डालने की अनुमति दी जाए क्योंकि वे अन्य राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर थे।

वोट डालने में रहे थे विफल : पुलिसकर्मी 19 अप्रैल को मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव के समय अपना वोट डालने में विफल रहे क्योंकि वे चुनाव ड्यूटी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गए थे।

सांसद वनलालवेना ने EC को लिखा पत्र : वनलालवेना ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में कहा कि वर्तमान में मिजोरम सशस्त्र पुलिस की 15 कंपनियों में 1,047 कर्मी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया। मिजोरम के सांसद ने कहा कि मिजोरम पुलिस के नोडल अधिकारी ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से पहले आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।

24 घंटे में केरल पहुंच रहा मानसून, झुलसाती गर्मी के बीच IMD ने दी अच्छी खबर; जानें आपके राज्य में कब मिलेगी राहत

देशभर में हीटेवेव की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इसी बीच आईएमडी ने जानकारी दी कि 30 मई को दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब सहित राजस्थान सहित बारिश हो सकती है। वहीं आईएमडी के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। हमारा अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे में मानसून केरल में आ सकता है।

नईदिल्ली। देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली-एनसीआर राजस्थान समेत कई राज्यों में तापामान 49 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने भयंकर गर्मी को देखते हुये लेबर एवं श्रमिकों के लिये दोपहर 12-3 बजे सवेतन छुट्टी रखने के आदेश दिए हैं। देशवासियों को मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया है।

अगले 24 घंटे में कारल आ सकता है मानसून : आईएमडी ने जानकारी दी कि 30 मई को दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान सहित बारिश हो सकती है। वहीं, आईएमडी के अनुसार, वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा, मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। हमारा अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे में मानसून केरल में आ सकता है।

इन राज्यों में हीटेवेव को लेकर अलर्ट : हालांकि, मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने जानकारी दी कि अगले दो दिनों के लिए बिहार, झारखंड और ओडिशा के लिए हीटवेव से गंभीर हीटवेव अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों के बाद बंगाल की खाड़ी से जब वहां नमी आएगी तो हालातों में सुधार होगा।

बीजेपी और बीजेपी के झूठ में न पड़ें और अपना भविष्य बर्बाद न करें , परिबार हित केलिए बोट कीजिये : डॉ अजय कुमार

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर : खाद्य सुरक्षा योजना में चावल, मनरेगा में कांग्रेस ने दिया रोजगार - केंद्र में इंडिया मेंट और ओडिशा में कांग्रेस, हर गरीब परिवार को सीधे मिलेंगे 26 हजार रुपये से ज्यादा प्रतिमाह ।इसलिए ओडिशा के लोगों, बीजेडी और बीजेपी के झूठ से मूर्ख मत बनो और अपना भविष्य देखो। अपने परिवार के अधिकारों के लिए वोट करें. पिछले 24 वर्षों के बिजेड़ी शासन और 9 वर्षों के बिजेड़ी-भाजपा शासन में जो नहीं किया जा सका, वह कांग्रेस ओडिशा के लोगों के लिए करेगी। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों को चावल, मिंडागरा के गरीब परिवारों को रोजगार दिया था। मोदी सरकार और नवीन पटनायक की सरकार सिर्फ कांग्रेस की योजना को अपने नाम पर बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है । इसलिए उनसे प्रभावित हुए बिना अपने भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दें, ऐसा ओडिशा प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ.अजय कुमार का कहना है। अजय कुमार ने फोन किया है । इस मौके पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल ओडिशा का दौरा करेंगे और भद्रक और बालासोर में दो भव्य जुलूस निकालेंगे । इसके अलावा डॉ. राहुल गांधी 30 तारीख को ओडिशा का दौरा करेंगे और भद्रक में चुनाव प्रचार करेंग अजय कुमार ने कहा ।मंगलवार को कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डॉ. अजय कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों को प्रति क्विंटल चावल पर 3000 रुपये एमएसपी के साथ बोनस दिया जाएगा, जिसे नवीन सरकार सिर्फ 17000 रुपये दे रही है । इसके अलावा कृषि ऋण माफ किया जाएगा और किसानों को 2000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा । इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली पर छूट दी जाएगी। इससे उन्हें प्रति माह 2 से 3 हजार रुपये की बचत हो सकती है ।5 लाखयुवक-युवतियों को रोजगार, स्नातक और डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवक-युवतियों को 30000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस ने बैंक कर्ज माफी, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग भत्ता बढ़ाकर 2000 रुपये करने का ऐलान किया है. खुलमाक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये और एससी, एसटी परिवारों की महिलाओं को 3,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। कांग्रेस ने राजस्थान की तरह ओडिशा में भी सभी को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है ।अगर कांग्रेस ओडिशा में सत्ता में आती है, तो हर परिवार को एमएसपी, बिजली बिल माफी, महिलाओं के लिए भत्ता, बेरोजगारी भत्ता आदि सहित सीधे 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। केंद्र में भारत सरकार आने पर हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक को पहली नौकरी मिलेगी । उन्हें प्रति माह 8 हजार 300 रुपये मिलेंगे , वहीं परिवार की महिलाओं को भी 8 हजार रुपये से ज्यादा मिल सकते हैं । इसलिए, अगर ओडिशा में कांग्रेस और इंडिया मेंट की सरकार आती है, तो हर गरीब परिवार को प्रति माह 26 हजार रुपये से अधिक जरूर मिलेंगे। अजय कुमार ने कहा ।

नवीन पटनायक की सरकार ने पिछड़े वर्ग को जितना धोखा दिया है, उतना किसी सरकार ने नहीं दिया । क्योंकि ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मोदी सरकार में पिछड़े वर्ग को सिर्फ 11 फीसदी आरक्षण दिया गया है । लेकिन इस वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए, उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए, कांग्रेस 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा करती है। इसी तरह कांग्रेस 100 दिन के भीतर जातीय जनगणना कराने की गारंटी दे रही है ।

दिल्ली हाई कोर्ट के दो और छत्तीसगढ़ के एक न्यायाधीश का तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

दिल्ली हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों और छत्तीसगढ़ हाई कार्ट के एक न्यायाधीश का बुधवार को विभिन्न हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गत 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस संजीव सचदेवा को क्रमश कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों और छत्तीसगढ़ हाई कार्ट के एक न्यायाधीश का बुधवार को विभिन्न हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गत 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस संजीव सचदेवा को क्रमशः कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी।

कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

कलेजियम ने दोनों न्यायाधीशों के स्थानांतरण के अनुरोध पर सिफारिश की थी। वहीं, कलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल को पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने कलेजियम से मद्रास हाई कोर्ट नहीं भेजने का अनुरोध किया था।

देवली कलां में बिजली का तार दंपती पर गिरा, युवक की गर्दन कटी: पत्नी की भी हालत गंभीर; पेड़ की टहनी गिरने से टूटा था बिजली का तार

ब्यावर रायपुर मारवाड़ के देवली कला में बुधवार को दोपहर में एक बिजली पोल से तार टूटकर बाइक सवार दंपती पर जा गिरा। तार में फंसने से युवक की गर्दन कटकर अलग हो गई। वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। जिसे रायपुर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक इलाज देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। ये घटना कस्बे के देवली कलां के पास दोपहर करीब 12:30 बजे हुई।

मौके पर ग्रामिणो ने बताया कि, गांव के ही कतीरिया बेरा निवासी सुरेश कुमावत अपनी पत्नी पांचू देवी को लेकर उसके ससूराल पीपलिया कलां जा रहे थे। करीब 1.5 किलोमीटर दूर ही चले थे कि सुरेश कुमावत के गले से बिजली के तार अटक गई और उसकी गर्दन कट गई। वहीं उसकी पत्नी पांचू देवी करंट लगने से झुलस गई जिसका उपचार एम डी एम होसपिटल जोधपुर में जारी है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में काफी रोष नजर आया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जुटने लगे हैं। ग्रामिणो ने पचास लाख मुहावाजावा , इनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी, एवं लापरवाही कर्मचारियों को खिलाफ कार्रवाई करने, एवं परिवार को अन्य सहयोग करने कि मांग। ग्रामिणो का धरना जारी एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए जैतारण एक्सईएन, एईएन के साथ कुशालपुरा चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर रहे है।

चुनावों में हेलिकॉप्टर के किराए में 50% का उछाल हर घंटे का वसूला 3 लाख, ऑपरेटर्स मालामाल

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

लोकसभा चुनावों में नेताओ द्वारा हेलिकॉप्टर्स की बढती डिमांड के चलते किरायों में बेतहाशा वृध्दि हो गई है।

उडनखटोले की मांग में इजाफा होने के चलते हेलिकॉप्टर के ऑपरेटर्स ने चार्टर्ड दरों में 50 फीसदी से ज्यादा तक किराए में बढोतरी कर दी है।

उल्लेखनीय है कि देश में लोकसभा चुनाव जारी है। अब-तक 6 चरण कंपलीट हो चुके हैं ।अब सिर्फ आखिरी 7 वें चरण की वोटिंग शेष है ।उसके बाद 4 जून को चुनावी नतीजे आ जाएगें। इस चुनावी मौसम में हेलिकॉप्टर ऑपरेटर्स खूब मुनाफा बटोर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 4 जून के करीब आते -आते इनकी कमाई का आंकडा 400 से 500 करोड रूपए तक पहुंच सकता है। आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान हेलिकॉप्टर की डिमांड में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। इस बार भी ये ही सूरत सामने हैं। चुनावी मौसम के आते ही तमाम तरह के बिजनेस जोर पकडने लगते हैं। इनमें होर्डिंग, बैनर, टेंट कुर्सिया, माइक, से लेकर नेताओ के प्रचार अभियान में शामिल हेलिकॉप्टर्स ऑपरेटरों के लिए खासा बिजी शिड्यूल रहता हैं। हेलिकॉप्टर चार्टरिंग दरें भी 50 % तक की लकीर को पार कर जाती है ।बता दें कि हेलिकॉप्टर को प्रति घंटे के हिसाब पर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्विन इंजन वाले 8 सीटर हेलिकॉप्टर की लागत हर घंटे करीब 3 लाख रूपये होती है। इस बार के चुनाव में 3 लाख रूपये घंटे के हिसाब ये 180 घंटों के प्रति हेलिकॉप्टर का किराया करीब 4-5 करोड रूपये होता है ।इस दौरान हेलिकॉप्टर आपरेटर्सर की कमाई पर गौर फरमाए तो ये आंकडा 400-500 करोड रूपए तक पहुंच सकता है। इसमें बताया गया है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 6-7 लोगों के बैठने की क्षमता वाले BEL-407 जैसे सिंगल इंजन वाले उडनखटोले का किराया बढकर 1.3 -1.5 लाख रूपये प्रति घंटा हो गया है। वहीं 7-8 लोगों की क्षमता वाले ऑगस्ताAW109 और H145 एयरबस हेलिकॉप्टर के किराये में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। जो प्रति घंटा 2.3-3लाख रूपये तक पहुंच गया । चुनाव अभियान के लिए किराए पर लिए जाने वाले हेलिकॉप्टर की लिस्ट में तीसरे कॉन्फिगरेशन में 15 सीटर ऑगस्ता वेस्टलैंड भी शामिल है। इनका किराया 4-5 लाख रूपये प्रति घंटे से शुरू होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक करीब 165-170 नॉन शेड्यूल ऑपरेटर (एनएसओपी है ।एनएसओपी का कोई विशेष निर्धारित कार्यक्रम नही होता है। और जब भी जरूरी होती है वे उडान भरते हैं। 2019 के चुनाव में 20-30 फीसदी किराए में उछाल आया था। लेकिन 2024 के चुनाव में हेलिकॉप्टर की डिमांड में बढोतरी के चलते किराए में करीब 50 फीसदी का उछाल है। जबकि हेलिकॉप्टरो की संख्या में वृध्दि नही हुई है।

इसी के मद्देनजर ही हेलिकॉप्टर ऑपरेटर्सर की मोटी कमाई हो रही है। दरअसल चुनाव के दौरान ये हेलिकॉप्टर ऑपरेटर 45-60 दिनों के लंबे पीरियड के लिए एग्रीमेंट साइन करते है ।इस अवधि के दौरान न्यूनतम 2-3-5 घंटे होते हैं। अगर कोई 60 दिन का अग्रीमेंट करता है तो फिर इस हिसाब से ऑपरेटर को 180 घंटे की उडान मिलती है। इसके बाद चाहे किराए पर लिए गए ये हेलिकॉप्टर उडान भरे या नहीं। पार्टी को भुगतान करना ही होता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023